● वर्ष-4
● अंक-139
रायपुर, मंगलवार 21 जनवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6 » फलदायी होती हैं हनुमान चालीसा की ...

निकाय और पंचायत चुनाव का ऐलान,

11 फरवरी को मतदान, 15 को परिणाम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होंगे। यानी 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव होंगे और 15 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय चुनाव के लिये मतगणना होगी। वहीं पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराये जाएंगे। यानी 17, 20, 23 फरवरी को होंगे पंचायत चुनाव के वोटिंग कराये जाएंगे। नगर निगम, पालिका और नगर पंचायत के चुनाव परिणाम 15 फरवरी को जारी होंगे, जबकि जिला पंचायत के परिणाम चुनाव के तुरंत बाद जारी हो जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 22 से 28 जनवरी तक नामांकन शुरू हो जायेगा। 24 फरवरी तक निकाय चुनाव संपन्न हो जायेंगे। इसी के साथ डी छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो चुकी है। नगरीय निकाय के लिये दो दिन बाद यानी 22 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।

नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होगा और ग्रामीण क्षेत्र के निकाय में तीन चरणों में मतदान होगा. 22 तारीख से प्रक्रिया शुरु होगी और उसी दिन से नॉमिनेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरु होगी. जो 31 जनवरी तक चलेगी. इसके बाद स्क्रूटनी और नाम वापसी के तारीख के बाद नामों की घोषणा होगा. 11 फरवरी को शहरी क्षेत्र में मतदान होगा और 15 फरवरी को मतगणना होगी.

पंचायत क्षेत्र में 27 जनवरी से नॉमिनेशन 3 फरवरी अंतिम तारीख 4 तारीख स्क्रूटनी, 6 फरवरी को नाम का ऐलान होगा.17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा. 18 20 और 24 फरवरी को टेबुलेशन होगा.इसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष पद का चुनाव होगा.

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल 184 निकाय हैं. जिसमें 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायत है.नगर निगम के चुनाव ईवीएम से और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से होंगे. प्रदेश में नगरीय निकायों के अन्तर्गत 10 नगरपालिक निगम, 49 नगरपालिका परिषद्, 114 नगर पंचायतों में आम निर्वाचन और जिला दुर्ग एवं सुकमा के नगरीय निकायों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 05 वार्डों में उप निर्वाचन सम्पन्न कराया जाएगा. साल 2019 की तुलना में इस बार 12 फीसदी से ज्यादा मतदाताओं में वृद्धि हुई है.

नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन में 2200525 पुरुष निर्वाचक, 22,73,232 महिला निर्वाचक, 512 अन्य निर्वाचक, कुल 44,74,269 निर्वाचक एवं उप निर्वाचन में कुल 16,181 निर्वाचक निर्वाचन में हिस्सा लेंगे. मतदान के लिए आम निर्वाचन के लिए कुल मतदान केन्द्र 5,970 और उप निर्वाचन के लिए कुल 22 मतदान केन्द्र निर्धारित किए गए हैं. जिनमें से 1531 संवेदनशील और 132 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र हैं.

भारत में नौकरियों पर हुई शोध ने चिंता बढ़ाई

नई दिल्ली। पेशेवरों को ध्यान में रखकर बनी सोशल मीडिया नेटवर्क लिंक्डइन के नए शोध के अनुसार, भारत में बड़ी संख्या में पेशेवर इस साल नई नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन यह तलाश अब पहले से कहीं अधिक कठिन हो गई है। दो तिहाई से अधिक (69 प्रतिशत) भारतीय मानव संसाधन पेशेवरों का मानना है कि किसी भूमिका के लिए योग्य प्रतिभाओं को ढूंढना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। शोध के अनुसार 2025 में पेशेवरों के लिए नौकरी के लिए आवेदन करने और नौकरी पाने के तरीके में कई बदलाव आए हैं।

नौकरियों के आवेदन अधिक हो रहे, पर जवाब कम आ रहा

लिंक्डइन के अनुसार, 49 प्रतिशत नौकरी चाहने वाले पहले से कहीं अधिक नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रतिक्रिया कम मिल रही है। नौकरी देने वालों के लिए भी यह

स्थिति चुनौतीपूर्ण है। लिंक्डइन ने बताया है कि एक-चौथाई (27 प्रतिशत) से ज्यादा एचआर पेशेवर आवेदनों की समीक्षा करने में प्रतिदिन 3 से 5 घंटे बिताते हैं और 55 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें मिलने वाले नौकरी आवेदनों में आधे से भी कम सभी मानदंडों को पूरा करते हैं।

लिंक्डइन इंडिया की करियर विशेषज्ञ और वरिष्ठ प्रबंध संपादक नीरजिता बनर्जी ने कहा, बाजार में नौकरी मिलना कठिन हुआ है। शोध के निष्कर्ष भारतीयों नौकरीपेशा लोगों को नौकरी की तलाश में अधिक सोच-समझकर कदम उठाने के लिए चेता रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अधिक रणनीतिक और सोच-समझ कर कदम उठाने से आपको चुनौतीपूर्ण नौकरी बाजार में भी नए अवसर और करियर में सार्थक सफलता मिल सकती है।

यह शोध सेंससवाइड की ओर से 27 नवंबर से 16 दिसंबर, 2024 के बीच 22,010 उत्तरदाताओं के बीच और 28 नवंबर से 18 दिसंबर, 2024 के बीच 8,035 वैश्विक मानव संसाधन पेशेवरों के बीच सर्वे के बाद तैयार की गई है। जहां यह सर्वे किया गया उन देशों में यूके, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, भारत, स्पेन, ब्राजील, आयरलैंड, नीदरलैंड, सिंगापुर, जापान, स्वीडन, सऊदी अरब, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इटली शामिल थे। भारत में 5 में से 3 पेशेवरों का कहना है कि वे किसी नए उद्योग या क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हैं।

राष्ट्रपति अप्रैल में आएंगी छत्तीसगढ़

डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा में प्रबोधन के लिए दिया न्योता

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी ने महामहिम राष्टपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से नई दिल्ली स्थित राष्टपति भवन में शिष्टाचार मुलाकात की ।इस विशेष अवसर पर डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने की जानकारी देते हुए माननीय राष्टपति महोदया को राज्य के विकास और संस्कृति से अवगत कराया व छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने महामहिम राष्टपति जी को आगामी अप्रैल माह में

विधानसभा में प्रबोधन के लिए आमंत्रित किया। जिसपर राष्टपति महोदया ने स्वीकृति प्रदान की है, इस विषय पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि राष्टपति महोदया की उपस्थिति छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए प्रेरणादायक होगी और राज्य की जनता के लिए गौरव का विषय बनेगी।

महाकुंभ में बाबा कर रहे ध्यान आकर्षित

नईदिल्ली। कई वर्षों के बाद आए महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है। महाकुंभ मेला भारत की सनातनी परंपराओं का सबसे बड़ा संगम है। महाकुंभ मेले में सिर्फ आस्था लिए हुए श्रद्धालु ही नहीं आते हैं बल्कि संन्यासियों, नागा बाबा, संतों का जमावड़ा भी कुंभ मेले में लगता है। महाकुंभ के दौरान संगम के तट पर ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जो वास्तव में हमने महसूस ना की हो। महाकुंभ में इस वर्ष कई बाबाओं ने शिरकत की है जो अपनी अनूठी जीवनशैली तो कोई अपनी तपस्या के कारण लोगों का ध्यान खींच रहा है।

बांसुरी बाबा ने खींचा ध्यान

इस महाकुंभ में पंजाब के पटियाला से आए ईश्वर बाबा सबका ध्यान खींच रहे है। महाकुंभ में उनकी अनोखी कला के कारण लोग आकर्षित हुए है। उनकी कला इतनी अनोखी है कि वो एक साथ दो दो बांसुरी बजा सकते हैं, जबकि कई लोग एक बांसुरी बजाने में भी सफल नहीं हो पाते है। उनकी खासियत है कि वो नाक से भी बांसुरी बजाना जानते है। ईश्वर बाबा मूल रूप से जूना अखाड़े से जुड़े हुए है। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें लोग बांसुरी बाबा कहते है। उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लंबी कतार में लोग लगे दिखते है।

सनातन का प्रचार

राजस्थान के हल्दीघाटी से आए शबदजाल भट्टारक बीते 56 वर्षों से सनातन धर्म के प्रचार में जुटे हुए है। मूल रूप से वो देश भर में घूमकर लोगों को एकजुट करते है। उनका मूल काम वैदिक संविधान लिखना है, जिसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। उनका कहना है कि सिर्फ 48 साधक ही है दुनिया में जो उनकी तरह साधना में जुटे हुए है।

मारुति बाबा

मध्यप्रदेश के भिंड से आए एक बाबा को मारुति बाबा कहकर लोग बुलाते है। उनका नाम मारुति कार के कारण ही मारुति पड़ा है, जिससे उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया है। वो अपने पास आने वाले भक्तों को आयुर्वेदिक चाय देते है, जो भक्तों के लिए प्रसाद का ही स्वरुप है। उनका दावा है कि इस चाय का सेवन करने से बीपी, शुगर जैसी बीमारियां ठीक होती है।

प्रमुख समाचार

बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

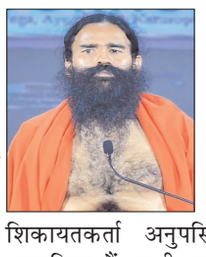

नई दिल्ली। केरल की एक अदालत ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में योग चिकित्सक बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और दिव्य फार्मेसी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। पलक्कड़ में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वितीय ने व्यक्तिगत

उपस्थिति के लिए समन जारी होने के बावजूद अदालत में उपस्थित होने में विफल रहने के बाद 16 जनवरी को वारंट जारी किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता अनुपस्थित है। सभी आरोपी अनुपस्थित हैं। सभी आरोपियों को जमानती वारंट दिया गया है। यह मामला पतंजलि आयुर्वेद की सहायक कंपनी दिव्य फार्मेसी द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसने कथित तौर पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 का उल्लंघन किया था। विज्ञापनों पर बीमारियों के इलाज के बारे में निराधार दावे करने और एलोपैथी सहित आधुनिक चिकित्सा को अपमानित करने का आरोप है। इसी तरह का एक मामला कोझिकोड में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित है।

ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त टिप्पणी की कि ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई 21 जनवरी तक टाल दी है,

जिन्होंने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। मामले में न्यायमूर्ति पंकज मिथल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने समय की कमी के कारण सुनवाई स्थगित कर दी, लेकिन जैसे ही दिन की कार्यवाही शुरू हुई, ताहिर हुसैन के वकील ने मामले का उल्लेख किया और 21 जनवरी को सुनवाई का अनुरोध किया। पीठ ने जवाब में टिप्पणी की, %जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है। ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए।% उनके वकील जानकारी देते हुए कहा कि ताहिर हुसैन का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 जनवरी को ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम के टिकट पर मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पैरोल दी थी।

रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर आई दिल्ली की सियासी लड़ाई

नई दिल्ली। दिल्ली की चुनावी सियासत रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के इर्द-गिर्द घुमती दिख रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि,क्क रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण देती है, अब इसका विरोध हो रहा है। सैफ अली खान के मामले से देश सदमे में है। अवैध घुसपैठियों

का समर्थन करने वाली आप जैसी पार्टियों पर बड़ा सवाल उठ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अवैध घुसपैठियों का समर्थन करने वाली पार्टी को चुनाव में बाहर कर देगी। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा कि आप नेताओं ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपना राशन कार्ड बनाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हिंसक हमले के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। खान पर उनके मुंबई स्थित आवास पर हुए हमले में एक बांग्लादेशी नागरिक शामिल था।

सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जवान बलिदान

जम्मू। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में रविवार देर शाम सुरक्षाबलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। गुज्जरपति जलूरा इलाके में तलाशी अभियान के दौरान यहां छिपे आतंकियों ने सेना व पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने

इलाके को पूरी तरह सील कर दिया है। यहां दो आतंकियों के घिरे होने की सूचना है। जिसमें एक जवान का बलिदान हो गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, रविवार दोपहर सोपोर के गुज्जरपति जलूरा इलाके में सेना की 22 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) व जम्मू-कश्मीर पुलिस संयुक्त तलाशी अभियान चला रही थी। इस दौरान छिपे आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों के अनुसार, तलाशी अभियान जारी है। सोमवार सुबह पहली किरण के साथ अभियान तेज किया जाएगा। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से स्थानीय लोगों से मुठभेड़ स्थल के करीब नहीं जाने का अनुरोध किया है। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले में शनिवार को चार सक्रिय आतंकियों के पोस्टर जारी किए गए थे।

भारतीय सेना ने किया डेविल स्ट्राइक का अभ्यास

नई दिल्ली। भारतीय सशस्त्र बलों ने 16 से 19 जनवरी तक आयोजित एक उच्च तीव्रता वाले संयुक्त अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस महत्वाकांक्षी अभ्यास, डेविल स्ट्राइक, जिसमें सेना के विशिष्ट हवाई सैनिक और वायु सेना शामिल थे। निर्बाध एकीकरण, उन्नत क्षमताओं और संचालन के लिए तत्परता का प्रदर्शन किया। रणनीतिक प्रशिक्षण क्षेत्रों और फायरिंग रेंजों में आयोजित, यह अभ्यास जटिल परिचालन परिदृश्यों को मान्य करने पर केंद्रित था, जिसमें शत्रुतापूर्ण इलाकों में सैनिकों और उपकरणों की सटीक प्रविष्टि शामिल थी। अभ्यास में विषम परिस्थितियों में परिचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक भरण-पोषण रणनीतियों का भी परीक्षण किया गया। अभ्यास का मुख्य आकर्षण अत्याधुनिक उपकरणों और उन्नत प्रौद्योगिकियों की तैनाती थी, जिससे दूरदराज और चुनौतीपूर्ण स्थानों पर बलों की सटीक और कुशल डिलीवरी संभव हो सकी। समकालिक हवाई अभ्यासों ने सेना और वायु सेना के बीच असाधारण समन्वय प्रदर्शित किया, जो एक एकजुट इकाई के रूप में काम करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, अभ्यास में यथार्थवादी मिशन परिदृश्यों को शामिल किया गया, जिससे सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता और प्रतिक्रिया तंत्र को परिष्कृत करने में मदद मिली।

राष्ट्रपति हद की शपथ ली, नाचते-नाचते ट्रंप ने कर दिए 3 बड़े ऐलान

नईदिल्ली। अमेरिका में क्डोनाल्ड ट्रंप राष्टपति पद की शपथ ली। शपथ लेने से पहले ट्रंप ने एक विक्ट्री स्पीच दी है। इस विक्ट्री स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने तीन नए ऐलान किए जिसे सुनकर लोगों को पीएम मोदी की याद आ गई। कुछ लोग तो यहां तक बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो पीएम मोदी वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। उसी फॉर्मूले पर काम करके डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्टपति बनने में काफी मदद मिल गई। ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका को फिर से महान देश बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का नारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पीएम मोदी की रणनीति से मेल खाता है। पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के कुछ समय बाद से ही ये बोलना शुरू कर दिया था कि वो भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। मोदी सरकार ने भारत को आगे बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशीकरण पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोगों में हिम्मत और क्षमता की कमी नहीं है। अब यही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कर दिखाया। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को वापस उसका गौरव दिलवाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया।

ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि हम अपने स्कूलों में देशभक्ती की भावना को दोबारा लाएंगे। यानी अमेरिकी लोगों के मन में देश के प्रति इज्जत और देशभक्ती होनी चाहिए। ठीक यही पीएम मोदी कर चुके हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में कहानियां सुनाई जो सच्चे देशभक्त हैं। पीएम मोदी ने उन लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। लोगों में देशभक्ति की भावना को

जगाने के लिए पीएम मोदी ने 2022 में ही हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि देश के सम्मान और तिरंगे से बढ़कर कुछ नहीं है। पीएम मोदी ने नौसेना को भी गुलामी के निशानों से मुक्ति दिलवाई और नौसेना से क्रास हटवा दिया। 26 जनवरी को गाई जाने वाली अबाइट विद मी की जगह ऐ मेरे वतन के लोगों गाया जाने लगा। मोदी सरकार ने ऐसे कई काम किए जो अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं।

ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका से लेफ्ट वामपंथियों को उखाड़ फेकेंगे। उन्होंने कहा कि हम सेना और सरकार को कट्टर वामपंथी विचारधारा से मुक्ति दिलाएंगे। ट्रंप के मुताबिक इसमें एजेंडा चलाने वाले पत्रकार, अखबार, इंफ्लूएंसर, एलजीबीटी क्यू, फेमनिस्ट लॉबी और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का इकोसिस्टम है। वो इस इकोसिस्टम को बर्बाद कर देंगे। हैरानी वाली बात है कि ठीक छह महीने पहले पीएम मोदी ने भी यही बयान दिया था। पीएम मोदी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला-फूला है। मैं आज इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं, मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं कि इस इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं कि उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। ये देश देशविरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा।

डरे चीन-अमेरिका और पाकिस्तान

अफगान में इन दिनों वर्चस्व की एक जंग चल रही है। इस जंग में भारत को जीतता देख कई देशों में बवाल खड़ा हो गया है। इस जंग में भारत जिस तरह से कूटनीतिक स्तर पर अफगानिस्तान में घुसा और पाकिस्तान को हराया। उसने चीन और अमेरिका के भी अब होश उड़ा दिए हैं। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और चीन अब तालिबान और भारत की दोस्ती तोड़वाने के लिए एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन चला सकता है। साल 2024 पिछले दस सालों में पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे ज्यादा खूनी साल रहा है। पाकिस्तानी सेना पर 500 से ज्यादा हमले हुए। इन हमलों में 1600 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तानी पुलिसवाले मारे गए। हैरान करने वाली बात ये है कि ये वही पाकिस्तान है जो 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का जश्न मना रहा था। खुशी के आंसू रो रहा था। लेकिन आज इसी तालिबान की वजह से पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है।

पाकिस्तान ने तालिबान पर दबाव बनाया कि वो भारत के खिलाफ एक्शन ले। मगर तालिबानी समझदार निकले। वो जानते थे कि फायदा भारत से मिलेगा न कि पाकिस्तान से। इसलिए तालिबान ने भारत के लिए पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया। भारत को खुश करने के लिए तालिबान ने पाकिस्तान की जो हालत की है, उसे देखकर चीन और अमेरिका भी घबरा गए हैं।

भाजपा सरकार अब सामान्य वर्ग को ठगने जा रही : कांग्रेस

बीजापुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला मुख्यालय बीजापुर में आयोजित प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए जगदलपुर के पूर्व महापौर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जतिन जायसवाल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ओबीसी के आरक्षण को बहाल करे। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों में भाजपा सरकार के द्वारा कराये गये वर्तमान आरक्षण प्रक्रिया के चलते प्रदेश में ओबीसी वर्ग का नुकसान हुआ है। इसलिए भाजपा सरकार आरक्षण को रद्द कर फिर से आरक्षण कराये और ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल करे, इसके लिये अध्यादेश लाना पड़े तो लाया जाये। विधानसभा की विशेष सत्र बुलाना पड़े, तो बुलाया जाये, लेकिन ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल किया जाये।

प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का एक भी सीट ओबीसी के लिये आरक्षित नहीं है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी ओबीसी वर्ग के आरक्षण में कटौती हो गयी है। कांग्रेस सरकार के समय 2019-20 में प्रदेश में जब जिलों की संख्या 27 थी तब अनुसूचित जनजाति के लिये 13, अनुसूचित जाति के लिये 3 ओबीसी के लिये 7 तथा सामान्य वर्ग के लिये 4 जिला पंचायत सीटें आरक्षित थी, भाजपा सरकार ने षड़यंत्रपूर्वक इसमें कटौती किया। अब जिलों की संख्या 33 हो गयी लेकिन ओबीसी का आरक्षण 7 से घटकर शून्य हो गया। प्रदेश के सभी जिला पंचायत एवं जनपदों में जहां पहले 25 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित हुआ करती थी, अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। भाजपा की साय सरकार के द्वारा आरक्षण प्रक्रिया के नियमों में किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के बाद अनुसूचित जिले, शहर और ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंचों का जो भी पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, अन्य वर्ग के लिये आरक्षित हो गया है।

जतिन जायसवाल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पहले ओबीसी को धोखा दिया, अब सामान्य वर्ग को ठगने जा रही। जब पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है तब कह रहे कि अनारक्षित वर्ग की आधा सीटों में पिछड़ा वर्ग को लड़ायेंगे। पहले तो पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार में डाका डाला, अब जले पर नमक छिड़क रहे।

जतिन जायसवाल ने प्रेस वार्ता में आगे कहा कि अनारक्षित सीटों में तो सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी लड़ सकता है और जहां पर जैसी परिस्थिति होती है लोग लड़ते भी है, इसमें भाजपा क्या अहसान कर रही? जतिन जायसवाल ने कहा कि ओबीसी वर्ग को भाजपा का अहसान नहीं बाबा साहब के संविधान के द्वारा दिया गया आरक्षण का अधिकार चाहिये।

निकाय चुनाव: टिकट मांगने युवाओं में होड़

■ पुराने चेहरों का कट सकता है पत्ता

धमतरी। नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई है। आज दोपहर राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जिसमें निकाय और पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इधर प्रदेश के निगमों में अलग अलग वार्डो से दावेदारी करने वाले युवा नेता सामने आने लगे हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा के सामने वार्डों में पार्षद और नगर निगम महापौर के लिए टिकट मांगने वालों की भीड़ दिखने लगी है।

पार्टी में सक्रियता रखने वाले और वार्डों में अपनी पहचान बनाने वाले नेता अब चुनाव रणभूमि में उतरना चाहते हैं। इस बार रणभूमि में ज्यादातर युवा आगे आ रहे हैं। इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि पुराने और बुजुर्ग हो चुके नेताओं की जगह अब युवा लेने लगे हैं। प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ी अब राजनीति में आने लगे है।

रविवार को धमतरी के रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा से अपनी दावेदारी को लेकर कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और आवेदन सौंपा। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के महामंत्री रामू रोहरा चूंकि धमतरी से हैं, इस वजह से धमतरी के युवा उम्मीदें और आवेदन लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं। धमतरी नगर निगम में 40 वार्ड है। इस बार महापौर के लिए भी चुनाव होने है। इसके लिए दावेदार सक्रिय हो गए हैं।

भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने बताया कि भाजपा की लोकतांत्रिक प्रणाली है। इस प्रणाली में सिस्टम है। वार्ड में पर्यवेक्षक जाते हैं। पर्यवेक्षक नाम देंगे, वो मंडल के जरिए जिले में जाएगा। जिले से संभाग में जाएगा। संभागीय चयन समिति टिकट तय करती है। भाजपा का संभागस्तरीय पैनल जो नाम तय करेगा वही सर्वमान्य है। उसे सबको मानना है। वार्ड में जिस व्यक्ति को भी टिकट दिया जाएगा, उसके लिए जी जान लगाकर भाजपा के पक्ष में मतदान कराकर जिताना है।

रामू रोहरा ने कहा 23 से 24 तारीख तक जिला चयन समिति एक बार बैठक कर नामों की सूची संभाग को भेजी। जिसके बाद नाम तय होगा। 24 से 25 साल के युवा भारी तादात में नगरीय निकाय चुनाव के लिए सामने आए हैं। जो राजनीति के लिए काफी अच्छा है।

प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने कहा कि बीते पांच साल छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा हुआ। प्रदेश में एक्सीडेंटल कांग्रेस की सरकार बनी और नगर निगम में भी कांग्रेस की सरकार बनी। अब सीधे चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक सालों से जीतते आए हैं। अभी भी स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 40 वार्ड में जीतने की योजना बनाई गई है। महामंत्री ने दावा किया कि धमतरी नगर निगम का महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। विष्णुदेव साय की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है। पूरा प्रदेश में सांय सांय विकास हो रहे है। उसी को देखते हुए जनता बीजेपी को मतदान करेगी।

भक्तों की यात्रा आसान करने रेलवे ने लिया बड़ा फैसला

महाकुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से 8 स्पेशल ट्रेन

बिलासपुर। महाकुंभ 2025 के लिए श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान देते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़, दुर्ग और बिलासपुर से वाराणसी के लिए 8 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेनें 25 जनवरी से 24 फरवरी के बीच अलग-अलग दिनों में चलाई जाएगी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के सीपीआरओ डॉ। सुस्कर विपुल विलासराव ने बताया, इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं को महाकुंभ के पवित्र स्नान का सपना पूरा करने का मौका भी देगा। छत्तीसगढ़ से वाराणसी तक की यह पहल श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी, जिससे उनकी यात्रा सुगम और आरामदायक होगी।

महाकुंभ 2025 के लिए ट्रेनों का शेड्यूल

- 08251 रायगढ़ - वाराणसी कुंभ स्पेशल प्रस्थान: 14:00 आगमन: 10:00, यात्रा दिनांक- 25 जनवरी 2025
- 08252 वाराणसी - रायगढ़ कुंभ स्पेशलप्रस्थान: 10:50 आगमन: 05:25, यात्रा दिनांक- 27 जनवरी 2025
- 08791 दुर्ग - वाराणसी कुंभ स्पेशल प्रस्थान: 13:50 आगमन: 10:00, यात्रा दिनांक- 8 फरवरी 2025
- 08792 वाराणसी - दुर्ग कुंभ स्पेशल प्रस्थान: 10:50 आगमन: 05:30, यात्रा दिनांक- 10 फरवरी 2025
- 08795 दुर्ग - टुंडला कुंभ स्पेशल प्रस्थान: 19:20 आगमन: 20:15, यात्रा दिनांक- 15 फरवरी 2025
- 08796 टुंडला - दुर्ग कुंभ स्पेशल प्रस्थान: 16:00 आगमन: 18:20, यात्रा दिनांक- 17 फरवरी 2025
- 08253 बिलासपुर - वाराणसी कुंभ स्पेशल प्रस्थान: 08:15 आगमन: 10:00, यात्रा दिनांक- 22 फरवरी 2025
- 08254 वाराणसी - बिलासपुर कुंभ स्पेशल प्रस्थान: 10:50 आगमन: 10:40, यात्रा दिनांक- 24 फरवरी 2025।

स्कूली बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर

हादसे में दो की मौत, 12 बच्चे घायल

कोंडागांव। कोंडागांव में स्कूली बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दो की मौत हुई है। वाहन चालक और एक शिक्षक की मौत की जानकारी मिल रही है। बस में सवार स्कूली बच्चों में से कुछ के घायल होने की खबर है। शासन ने जिला प्रशासन को बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।

दुर्घटना कोंडागांव सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चिकलपुटी के पास की है। बताया जाता है कि 12 बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें चार की हालत गंभीर है। यह हादसा कोंडागांव नेशनल हाईवे 30 पर हुआ। स्कूली बच्चे एक भ्रमण यात्रा से वापस आ रहे थे, तभी बस एक ट्रक से टकरा गई। बस में सवार सभी बच्चे और शिक्षक मोहला-मानपुर जिले के मिडिल स्कूल के बताये जा रहे हैं थे। बच्चे तीर्थगढ़, चित्रकूट, दंतेवाड़ा और बारसूर से भ्रमण के बाद लौट रहे थे।

सीएम साय ने घटना पर जताया दुख

कोंडागांव में स्कूली बस और ट्रक के बीच हुई सड़क दुर्घटना में वाहन चालक सहित एक शिक्षक के निधन की खबर अत्यंत दु:खद है। बस में सवार स्कूली बच्चों में कुछ बच्चों के घायल होने की भी खबर है, जिनका इलाज जारी है। जिला प्रशासन को बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने व घायल बच्चों के जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं।

जीएसटी अफसर का बेटा फ्रॉड केस में अरेस्ट

कॉलेज सीनियर से ही 36 लाख की ठगी की

दुर्ग। सुपेला थाना पुलिस ने बिटक्वाइन ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की ठगी करने के मामले में नागपुर में तैनात सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर के बेटे को गिरफ्तार किया है।आरोपी ने दुर्ग निवासी और बीआईटी कॉलेज दुर्ग की अपनी सीनियर से 36 लाख रुपए की ठगी की है। स्मृति नगर जुनवानी निवासी वैष्णवी नायर ने सुपेला थाने में 16 अगस्त 2024 को इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी।

वैष्णवी के मुताबिक वो साल 2016 में बीआईटी दुर्ग में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान उसके जूनियर तनमय विनोद कोहड़ निवासी न्यू वसुंधरा सोसायटी बेल तरोरी रोड नागपुर से हुई। वैष्णवी इंजीनियरिंग करने के बाद आईटी कंपनी पुणे में जॉब करने लगी। 2019 में अचानक एक दिन तनमय का फोन आया। उसने वैष्णवी से कहा कि उसने इंजीनियरिंग पूरी कर ली है। डिग्री लेने आया है। उनके ऑफिस में कोई जॉब है क्या। इस पर वैष्णवी ने कहा जॉब होगी तो उसे बताएगी। फोन पर बात करते करते ही तनमय ने वैष्णवी से कहा कि एक बिटक्वाइन ऑनलाइन ट्रेडिंग का गेम है। उसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। उसने वैष्णवी से लगातार फोन पर बात करते-करते 7800 रुपए लेकर उसमें इनवेस्ट करा दिए। कुछ दिन बाद उसने रिटर्न के रूप में वैष्णवी को 6500 रुपए का प्रॉफिट दिया।वैष्णवी इससे उसके बातों में आ गई। तनमय ने वैष्णवी से कहा कि इसमें बड़ा इनवेस्ट करोगे तो काफी बड़ा फायदा होगा।पैसा रिटर्न की वो गारंटी लेता है। वैष्णवी अपने जूनियर तनमय की बातों में आ गई। इसके बाद उसके खाते में 10 अगस्त 2020 से लेकर 28 अप्रैल 2022 के बीच तीन अलग-अलग ट्रांजेक्शन 73051 रुपए, 510362 और 3031299 रुपए डाल दिए। जब वैष्णवी ने अपना रिटर्न मांगा तो तनमय उसे घुमाने लगा। बाद वैष्णवी ने सुपेला थाने में केस किया।

फ्रॉड केस में अरेस्ट = केस करने के बाद स्मृति नगर और क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम तनमय को पकड़ने के लिए नागपुर गई। पुलिस की टीम उसके लोकेशन को ट्रैस कर उसके न्यू वसुंधरा सोसायटी बेल तरोरी रोड नागपुर पहुंची और उसे उसके घर से गिरफ्तार कर दुर्ग लाई है।

तनमय के पिता विनोद कोहड़ सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट में स्टेटिक्स डिपार्टमेंट में सुप्रीटेंडेंट हैं। विनोद इससे पहले भोपाल, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, दुर्ग, जगदलपुर, भांटापारा, बिलासपुर में इंस्पेक्टर के पद पर थे। प्रमोशन पाकर सुप्रीटेंडेंट बनने के बाद कुछ समय रायपुर फिर उसके बाद से नागपुर, कस्टम में गए और वर्तमान में नागपुर में ही हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

प्रयागराज से लौट रहा परिवार का कार पलटा पंडरिया में

कवर्धा। सेवानिवृत्त सेना का जवान चंद्रिका प्रसाद तिवारी अपने परिवार के साथ कार में प्रयागराज महाकुंभ दर्शन कर वापस लौट रहे थे कि उनकी कार पंडरिया बजाग मार्ग में हनुमंत खोल घाट के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार चालक चंद्रिका प्रसाद और सामने बैठे 2 लोगों को चोट आई है, बाकी सभी सुरक्षित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार चालक सेवानिवृत्त सेना का जवान चंद्रिका प्रसाद तिवारी बेमेतरा के रहने वाले हैं जो माता-पिता, पत्नी और दो बच्चों के साथ प्रयागराज महाकुंभ गए हुए थे। वहां से वापसी के दौरान उनकी कार पंडरिया बजाग मार्ग में हनुमंत खोल घाट के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद चीख पुकार मच गई और वहां से गुजर रहे लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर डायल 112 को फोन किया गया। इस घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक और सामने बैठे 2 लोगों को चोट आई है, बाकी सब सुरक्षित है। गनीमत रही कि कार खाई में नहीं गिरी वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।

ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर पुलिस-नक्सलियों में मुठभेड

नुआपाड़ा/गरियाबंद। सोमवार को विश्वसनीय रिपोर्टों में कहा गया है कि ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर पुलिस कर्मियों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई है। खुफिया जानकारी के आधार पर, ओडिशा पुलिस के एसओजी, छत्तीसगढ़ पुलिस के विशेष बल और सीआरपीएफ के संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान को 19 जनवरी से 20 जनवरी, 2025 की रात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कुलारीघाट रिजर्व फॉरेस्ट में लॉन्च किया गया। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि, ऑपरेशन का स्थान नुआपाड़ा जिले में ओडिशा की सीमा से 5।5 किमी दूर स्थित है। आज सुबह करीब 8ः30 बजे एसओजी और छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ गोलीबारी की सूचना मिली है, जो अभी भी जारी है। बीजापुर पुलिस ने कहा कि 12 जनवरी (रविवार) को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम तीन नक्सली मारे गए थे। सुरक्षाकर्मियों ने कई स्वचालित और अन्य हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए हैं।

महामाया पहाड़ पर अवैध कब्जा हटाने बुलडोजर एक्शन

अंबिकापुर। शहर के महामाया पहाड़ पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए आज प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। मौके पर राजस्व, वन विभाग के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में फोर्स पहुंची है। इस एक्शन के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ प्रदर्शन किया। पहले दिन की कार्रवाई में 60 घरों को तोड़ा जाना है। प्रशासन ने नवागढ़ इलाके के 60 घरों में कब्जा हटाने का नोटिस चस्पा किया था। जानकारी के अनुसार, प्रशासन की पहुंचने की सूचना पर कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्यवस्थापन करने की भी मांग रखी। समझाइश के बाद पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया। सिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर, सरगुजा से लगे महामाया पहाड़ को काटकर करीब 450 लोगों ने कब्जा कर कब्जाधारियों के मकान, बाड़ी बना लिया हैं। 2 दिन पूर्व नवागढ़ इलाके के 60 घरों में कब्जा हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया था। नोटिस दिए गए अन्य घरों को दूसरे चरण में तोड़ा जाएगा।

10वीं की छात्रा पर युवक ने किया चाकू से हमला

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक 10वीं कक्षा की छात्रा पर सिरफिरे युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। छात्रा स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान युवक ने छात्रा को रोक कर उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में छात्रा बुरी तरह घायल हो गई। जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने छात्रा की शिकायत दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि यह मामला एक तरफा प्रेम का है। आरोपी युवक ने छात्रा को प्रेम प्रस्ताव दिया लेकिन छात्रा के मना करने पर आरोपी ने आक्रोशित होकर छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया।

होटल में लग रहा था ताश पत्ती पर दांव, पुलिस का रेड

बिलासपुर। न्यायधानी बिलासपुर के एक होटल में पुलिस ने रेड मारकर 11 रसूखदार लोगों को रंगे हाथो जुआ खेलते पकड़ा। होटल के मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जुआरियों के पास से 3।50 लाख रुपए नकद जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक, सिविल लाइन पुलिस को रविवार की रात मुखबीर सूचना मिली कि होटल ईस्ट पार्क के रूम नम्बर 405 में रसूखदार लोग 52 परियों पर दांव लगा रहे हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम ने होटल ईस्ट पार्क पहुंची, यहां रोपी प्लास्टिक क्राईन (टोकन) का उपयोग कर जुआ खेला जा रहा था। पुलिस ने होटल में छापा मारकर 11 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 3 लाख 50 हजार 300 रूपये, ताश की गड्डी और प्लास्टिक क्राईन 350 नग को जब्त किया गया।

रैफिक जाम से कब मिलेगी राहत, दो दशकों से नहीं बन सका बस स्टैंड

7 साल बाद भी नहीं हो सका रिंग रोड का निर्माण कार्य

बलरामपुर। जिले के वाड्रफनगर नगर पंचायत स्थित बस स्टैंड में जाम लगने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। यहां आए दिन यातायात जाम की स्थिति निर्मित होने से महतारी एक्सप्रेस को भी गुजरने में दिक्तों का सामना करना पड़ता है। वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग से यातायात जवानों की तैनाती भी जाम के आगे फीकी पड़ जाती है।

दरअसल, तीन अलग-अलग प्रदेशों को जोड़ने वाले वाड्रफनगर का बस स्टैंड लगभग 22 वर्ष बाद भी आज तक नहीं बन सका है। वहीं जाम से निपटने के लिए रिंग रोड का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसका काम 7 साल में भी पूरा नहीं हो पाया है। इस वजह से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। क्षेत्र में विकास ही नहीं बल्कि ठेले और गुमटी भी जाम से परेशानी का सबब बने हुए हैं। अव्यवस्थित ठेले गुमटी के कारण लोग वाहनों को अव्यवस्थित पार्क कर देते हैं। जिसके चलते भी जाम की स्थिति निर्मित होती है। लेकिन ट्रैफिक जाम को ठीक से नियंत्रित करने में कामयाब नहीं हो पाते। इस मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष पति नंदलाल श्यमले ने कहा कि लॉन्ग रूट की बसें शाम के समय जब यहां लग जाती हैं तो आवागमन काफी प्रभावित होता है। कुछ ठेले-गुमटी वालो के चलते भी अवस्थित मोटरसाइकिल पार्क किया जाता है। पुलिस प्रशासन व नगर पंचायत को मिलकर इस पर कार्यवाही करना चाहिए। वहीं नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दयाशंकर गुप्ता ने बताया कि कुछ ठेले व गुमटी वाले अवैध रूप से ठेला लगा रहे हैं। जिससे यातायात प्रभावित हो रही है। तत्काल पुलिस प्रशासन से सहयोग लेकर इन्हें व्यवस्थित किया जाएगा ताकि आम लोगों को यातायात में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

पेड़ से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो

■ कार्यक्रम देकर गांव लौटते वक्त हादसे की शिकार हुई रामायण मंडली

बालोद। जिले में आज दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, ग्राम मनकी के रामायण मंडली के सदस्य रामचरित मानसगान का कार्यक्रम देकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में पति-पत्नी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पांच लोग घायल हुए हैं। मृतक दंपत्ति के दोनों बच्चों की हालत भी गंभीर है। यह घटना देवरी थाना क्षेत्र के मुजगहन और खामतराई गांव के बीच हुई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक, रामचरित मानस मंडली के लोग कार्यक्रम देने के बाद स्कॉर्पियो में सवार होकर अपने गांव मनकी लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में मनकी गांव के निवासी पुरषोत्तम यादव 43 वर्ष और उनकी पत्नी जानकी यादव 40 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के दोनों बच्चे हर्ष यादव और वीणा यादव गंभीर रूप से घायल हैं। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

सूरजपुर में मिला हाथी का शव वन विभाग जांच में जुटी

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के जंगल में सोमवार को एक हाथी मृत पाया गया। हाथी के मौते की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल, वन विभाग जांच में जुटी है।

वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक, सूरजपुर जिले में सुबह प्रतापपुर वन रेंज अंतर्गत बगदा वन क्षेत्र में करीब 12 साल के हाथी का शव मिला। वन कर्मियों ने मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में करीब 6 सालों में करीब 90 हाथियों की मौत हुई है। इनमें बीमारी और उम्र ढलने से लेकर बिजली का करंट लगने तक की वजहें शामिल हैं। राज्य के उत्तरी हिस्से में मानव-हाथी संघर्ष पिछले एक दशक से चिंता का बड़ा कारण रहा है। इस खतरे का सामना करने वाले जिले सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर और बलरामपुर हैं।

संक्षिप्त समाचार

स्वच्छता दीदियों के लिए मुख्यमंत्री साय ने की बड़ी घोषणा, मानदेय राशि में की वृद्धि

रायपुर। चुनाव आचार संहिता की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को दो बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने स्वच्छता दीदियों को हर माह 8000 रुपये का मानदेय राशि दिए जाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने रायपुर निगम के लिए 2 सौ करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। बता दें, स्वच्छता दीदियों को अब तक हर महीने 7200 रुपए का मानदेय दिया जाता था। मुख्यमंत्री साय ने इस राशि में 800 रुपए बढ़ाते हुए उन्हें 8000 प्रति माह दिए जाने की घोषणा की है।

कांग्रेस की बैठक में 35 विधायकों में 12 विधायक रहे गायब

रायपुर। नगरीय निकाय और पंचायत की तारीखों की घोषणा से पहले सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में राजीव भवन में विधायकों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एआईसीसी सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी जरिता लैतफलांग, एआईसीसी सह-सचिव एवं सह प्रभारी विजय जांगिड़, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर, अमितेश शुक्ल, गुरू रूद्र कुमार, अमरजीत भगत और अनिला भेडिया के साथ 23 विधायक शामिल है। कांग्रेस विधायकों की संख्या 35 है लेकिन 12 विधायक इस महत्वपूर्ण बैठक से गायब रहे इस बात की चर्चा बैठक में होते रही। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी तो वह वादे कौन-कौन से होंगे और इसका कितना लाभ चुनाव में पार्टी को मिलेगा, जनता इससे कितनी संतुष्ट होगी। इसके अलावा महापौर पद के साथ ही पार्षद प्रत्याशियों और पंच से लेकर सरपंच के पद पर किसे मैदान में उतारा जाना चाहिए।

समता और चौबे कॉलोनी के निवासियों के साथ धरने पर बैठे उपाध्याय

रायपुर। समता कॉलोनी और चौबे कॉलोनी

के निवासी नाली निर्माण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए है, उनके समर्थन में सोमवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी सड़क पर धरने में बैठ गए। निवासियों का कहना था कि इलाके में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में पानी सड़कों पर भर जाता है, जिससे आवागमन में दिक्कतें होती हैं। विकास उपाध्याय ने भी प्रदर्शनकारी लोगों का समर्थन करते हुए प्रशासन से तत्काल नाली निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

शहीद गेंदलाल ने ब्रिटिश हुकूमत की हिलाई थी नींव : सीएम साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार

को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अमर शहीद गेंद सिंह के शहादत दिवस पर उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने आजादी के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीद गेंद सिंह को याद करते हुए कहा कि परलकोट जमींदारी के जमींदार शहीद गेंद सिंह ने ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का शंखनाद किया था। ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। सीएम ने आगे कहा कि गेंद सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने क्षेत्र में अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम सभी शहीद गेंद सिंह का स्मरण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और समाज के उत्थान में अपना योगदान दें। बस्तर के आदिवासी भाई-बहनों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मुक्ति आंदोलन के नायक शहीद गेंदसिंह का मातृभूमि की मुक्ति के लिए दिया गया अविस्मरणीय बलिदान हम सभी को देशसेवा के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देते रहेगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय हलबा हलबी आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ केंद्रीय महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र महला, आईआर देहारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

दो सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 2.93 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। राज्य शासन ने दंतेवाड़ा जिले के अंतगर्त दो सिंचाई योजना के कार्यों के लिए 2 करोड़ 93 लाख 26 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत इन योजनाओं में दंतेवाड़ा जिले के विकासखंड-दंतेवाड़ा के चितालूर जलाशय के जीर्णोद्धार कार्य के लिए एक करोड़ 47 लाख 13 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। इसी तरह से विकासखंड गीदम के टेकनार जलाशय योजना के कार्यों के लिए एक करोड़ 46 लाख 13 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से सिंचाई योजनाओं के कार्यों को कराने के लिए मुख्य अभियंता महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का किया शुभारंभ

प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचे सुशासन का लाभ, यही हमारा प्रयास : साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों से किए गए वायदे के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कृषि भूमि भी नहीं है और वे कृषि मजदूरी कर जीविकोपार्जन करते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने भूमिहीन कृषि मजदूर भाई-बहनों से भी एक वादा किया था। हमने कहा था कि उन्हें 10 हजार रुपए सालाना आर्थिक सहायता देंगे। आज हमने इस वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज न्यू सर्किट हाउस स्थित आडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 5 लाख 62 हजार 112 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इस योजना के तहत पाँच सौ 62 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये हम भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि

पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने भूमिहीन मजदूर हितग्राहियों को 10 हजार रुपए की राशि का चेक वितरित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से प्रदेश के भूमिहीन मजदूर परिवारों के आर्थिक समृद्धि का जो संकल्प हमने लिया था, वह आज साकार हो रहा है। साय ने कहा कि यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का हर गरीब और भूमिहीन परिवार खुशहाल हो। यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता को जो गारंटियां दी थीं, उनमें से अधिकांश गारंटियों को हमारी सरकार ने महज एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। शपथ लेने के दूसरे दिन ही पहली कैबिनेट में हमने जरूरतमंद 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। हमारी सरकार ने पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब जिनके पास दुपहिया वाहन हैं, ढ़ाई एकड़ सिंचित भूमि या पाँच एकड़ असिंचित भूमि है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये है, वे भी पीएम आवास के लिए पात्र होंगे। हमने राज्य में आवास प्लस के लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक तक सुशासन का लाभ पहुँचे, हमारी सरकार का यही प्रयास है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इसी तरह मोदी की गारंटी के तहत हमने 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा किया था। हमारी सरकार ने किसानों से किया हर वादा निभाया। चालू खरीफ सीजन में हम किसानों से वादे के मुताबिक 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान खरीदी के साथ किया जा रहा है तथा अंतर की राशि फरवरी माह में प्रदान कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब किसान भाइयों को उनके उपज की पूरी कीमत मिल रही है तो खेती छोड़ चुके किसान भी कृषि की ओर लौट रहे हैं। हमने तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को चार हजार रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 55 सौ रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है, जिससे वनवासी क्षेत्र के 12 लाख 50 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक बंधु लाभान्वित हो रहे हैं। हमने मोदी की गारंटी के तहत माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना में एक हजार रुपये प्रति महीने देने का वादा किया था। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब तक 11 किश्तों में माताओं-बहनों को 7 हजार 182 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसी तरह रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना को शुरू कर अब तक छत्तीसगढ़ से 20 हजार श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम दर्शन के लिए हम भेज चुके हैं। एक-एक कर हम मोदी की गारंटी के तहत किए गए हर वादे को पूरा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएँ संचालित कर रही है। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ हितग्राही समूह तक पहुँचे। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे किए वादे का लाभ आप तक पहुँच रहा है और हमारे प्रयासों से आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जब से प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हुआ है। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में हमारी सरकार ने बड़ी योजनाओं को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल के सपनों को हमारे मुख्यमंत्री साकार कर रहे हैं।

इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक सुनील सोनी, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, प्रभारी मुख्य सचिव रेणु पिल्ले, राजस्व विभाग की सचिव शहला निगार सहित वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी और प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हितग्राहीगण उपस्थित थे।

बर्खास्त सहायक शिक्षकों पर साय का बड़ा बयान

■ कहा नहीं चाहते जाए किसी की नौकरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बर्खास्त सहायक शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है।सीएम साय ने कहा कि वो नहीं चाहते कि सहायक शिक्षकों की नौकरी जाए।सीएम साय के मुताबिक वो सहायक शिक्षकों की बेहतरी चाहते हैं।आपको बता दें कि बीएड डिग्री धारी सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक सूत्रीय मांग अपनी नौकरी की वापसी है।इसके लिए वो किसी भी विभाग में समायोजित होने के लिए तैयार हैं। नौकरी की मांग को लेकर सहायक शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इसके लिए कमेटी बनाई जाने से वह संतुष्ट नहीं है ,ये अलग बातें हैं।

विष्णुदेव साय ने कहा हम लोग भी उनकी बेहतरी चाहते हैं।सीएस की अध्यक्षता में हमने कमेटी का गठन

किया है और उस कमेटी की सिफारिश आएगी। हम भी नहीं चाहते कि उनकी नौकरी जाए ,लेकिन कोई भी चीज नियम और प्रक्रिया से होती है।

रविवार रात सहायक शिक्षकों ने तेलीबांधा तालाब में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और सहायक शिक्षकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। सहायक शिक्षकों का कहना है कि कहना कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।तेलीबांधा में प्रदर्शन के दौरान महिला सहायक शिक्षकों ने पुलिस पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। इस दौरान रात को रायपुर पुलिस कर्मी टीचर्स को धरनास्थल से हटाने की कोशिश करने लगे। जिसके बाद पुलिस और सहायक शिक्षकों के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई। महिला सहायक शिक्षकों ने आरोप लगाए कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। शिक्षकों के मुताबिक रात को उन्हें बिना किसी लेडी कॉन्सटेबल की मदद के हटाया गया। पुरुष पुलिसकर्मियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की।यही नहीं नशे की हालत में दुर्व्यवहार भी किया। प्रदर्शनकरियों ने कपड़े फाड़ने का भी आरोप लगाया है। सहायक शिक्षकों और पुलिस की धक्कामुक्की में कुछ सहायक शिक्षिकाएं बेहोश भी हो गई थी।

अप्रैल के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू

■ डॉ. रमन सिंह ने की मुलाकात, दिया न्यौता

रायपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अप्रैल के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ आयेंगी। वे विधानसभा के प्रबोधन सत्र को संबोधित करेंगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रपति से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। उन्हें छत्तीसगढ़ आने के लिये न्यौता दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर छत्तीसगढ़ आने के लिये अपनी स्वीकृति दे दी है।

इस अवसर पर रमन ने छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति को राज्य के विकास और संस्कृति से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को अप्रैल में विधानसभा में प्रबोधन के लिए आमंत्रित किया। इस पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति की उपस्थिति छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए प्रेरणादायक होगी और राज्य की जनता के लिए गौरव का विषय बनेगी।

इससे पूर्व रमन सिंह ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। स्पीकर ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया कि नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मंडविया से सौहार्दपूर्ण भेंटकर छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव में खेल जगत के उत्थान से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और खेल से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने पर सार्थक संवाद हुआ।

भाजपाइयों ने पार्षद के दावेदार के खिलाफ खोला मोर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुम्हारी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और अन्य नेताओं को पत्र लिखकर कुम्हारी नगर पालिका के वार्ड 14 से भाजपा के पार्षद पद के दावेदार राकेश पांडे का खुलकर विरोध किया है। उनका कहना है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देने से पार्टी की छवि पर नकारात्मक असर पड़ेगा। कुम्हारी भाजपा कार्यकर्ता सात्विक तिवारी ने पत्र में कहा कि राकेश पांडे के खिलाफ 2017 में लकड़ी तस्करी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें गंभीर धाराएं लगाई गई थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि पांडे को जेल की सजा भी हुई थी और वर्तमान में वह जमानत पर बाहर हैं। इसके अलावा उन पर नहर की भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप भी लगाए गए हैं। सिचाई विभाग द्वारा अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन पांडे ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर कब्जा नहीं हटवाया। सात्विक तिवारी ने पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसे लोग जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं और राजनीति का उपयोग अपने अपराधों को संरक्षण देने के लिए करते हैं, उनका पार्टी में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पार्टी के सिद्धांतों और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए।

चुनावी खर्चों पर आयोग की नजर, प्रत्याशियों के लिए सीमा निर्धारित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से होंगे, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की पैनी नजर सभी प्रत्याशियों के चुनाव में होने वाले खर्चों पर भी रहेगी।

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मेयर और अध्यक्षों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में मेयर प्रत्याशी 25 लाख, 3-5 लाख की आबादी वाले नगर निगम के लिए यह सीमा 20 लाख और 3 लाख से कम आबादी वाले निगम 15 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे।

नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए चुनावी खर्च की राशि तय

वहीं, 50 हजार से अधिक आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 10 लाख रुपए और 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 8 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए खर्च

की सीमा 6 लाख रुपए है।

पार्षदों के लिए चुनावी खर्च की राशि निर्धारित

ऐसे नगर निगम, जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है वहां पार्षद 8 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकेंगे। वहीं में 3 लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों में खर्च की सीमा 5 लाख रुपए होगी। वहीं नगर पालिका में पार्षदों के खर्च की सीमा 2 लाख और पंचायतों में 75 हजार निर्धारित की गई है।

बता दें कि अभी 14 नगर निगमों में से 10 नगर निगम, 54 नगर पालिकाओं में 45 के नगरपालिका परिषद और 124 नगर पंचायतों में से 114 नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए चुनाव होंगे।

आचार संहिता में इन बातों का रखना होगा ध्यान

1. प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसे लेकर राज्य शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है।

2. आचार संहिता से संबंधित विषय पर तत्कालिक निर्णय लेना आवश्यक हो तो राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श कर निर्णय लिया जाए।

3. कर्मचारियों व अधिकारियों को कलेक्टर की बिना अनुमति के अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। नियुक्ति व पदस्थापना भी प्रतिबंधित रहेगी।

4. सरकार के मंत्री कोई घोषणा नहीं कर पाएंगे और न ही भूमिपूजन या लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे।

5. लाउडस्पीकर के उपयोग, वाहनों की व्यवस्था, विश्रामगृहों व भवनों में कमरों का आरक्षण, निर्वाचन के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था, शिकायतों के निराकरण, स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध आदि के संबंध में भी दिशा-निर्देश।

किसानों को सक्षम बनाने में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं कृषि वैज्ञानिको का है महत्वपूर्ण योगदान : मंत्री नेताम

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 39 में स्थापना दिवस में शामिल हुए कृषि मंत्री, रामविचार को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान

रायपुर। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि मेहनतकश किसानों को सक्षम बनाने में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं कृषि वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी का परिणाम है कि आज किसान उन्नत कृषि तकनीक का उपयोग कर आत्मनिर्भर बन रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों की उन्नति एवं समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार देश के अन्य राज्यों की तुलना में किसानों को धान का वाजिब मूल्य प्रदान कर उनका सम्मान बढ़ाया है। मंत्री श्री नेताम आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वद्यालय के 39वां स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उक्त बाते कही।

इस मौके पर विश्वद्यालय द्वारा मंत्री श्री रामविचार नेताम को राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए लॉइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही कृषि एवं शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट

योगदान के लिए कुलपति डॉ. गिरिश चन्देल, किसान श्री नारायण भाई चावड़ा, शिक्षक श्री बी.आर. चन्द्रवशी तथा डॉ. एम.एन श्रीवास्तव भी लॉइफ टाइम अचीमेंट पुरस्कार से सम्मानित हुए। मंत्री श्री नेताम इस अवसर पर कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक अनुसंधान पहल विषय पर आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री नेताम ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सहित देश के किसानों को कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र में और कैसे सक्षम बनाया जाए इस दिशा में कृषि वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों को सोचने की जरूरत है हमारी सरकार किसानों को सक्षम बनाने के लिए किसान हित में बहुत से फैसले लिए है। हमारी सरकार ने किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तथा 31 सौ रूपए प्रति क्विंटल के मान धान खरीद कर किसानों को देश में सर्वोच्च कीमत प्रदान कर रही है। वहीं किसानों को किए गये वायदों के मुताबिक लगभग 3800 करोड़ रूपए की बोनस राशि भी प्रदान की गई है। इससे प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हुए है।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि केशर, अखरोट सहित अन्य चिन्हाकिंत फसलों के लिए जम्मू-कश्मीर की अपनी एक अलग पहचान है। यह पहचान वहां के मेहनतकश किसानों के परिश्रम से बना है। वहां के किसान कॉपरेटिव सेक्टर बना कर एवं एग्रो से जुड़कर किस तरह से उन्नत कृषि कर रहें है। कार्यशाला में इस क बारे में भी जानने एवं समझने को मिलेगा उन्होंने इंदिरा कृषि विश्व विद्यालय के 39वें स्थापना दिवस एवं कार्यशाला के लिए बधाई एवं शुभकामानाएं दी कार्यशाला को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरिश चन्देल ने संबोधित किया। कार्यशाला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर एवं राष्ट्रीय कृषि विकास सहकारी लिमिटेड, बरामूला (जम्मू-कश्मीर) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी।

इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के 21 राज्यों के 400 से अधिक कृषि वैज्ञानिक एवं शोधार्थी शामिल है। सम्मेलन में वैश्विक परिदृष्य में भूमि, जल तथा पर्यावरण के क्षेत्र में विद्यमान अवसरों एवं चुनौतियों पर विचार मंथन कर संसाधनों का बेहतर उपयोग कर इनमें निरंतर होने वाली कमियों को सुधारने के रास्ते तलाशे जाएंगे।

सम्मेलन में संबंधित विषयों पर वैज्ञानिकों तथा शोधार्थियों द्वारा शोध पत्र तथा पोस्टर्स प्रस्तुत किया गया।

उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुई थी। इस विश्वविद्यालय को छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे विश्वविद्यालय अपने 28 कृषि महाविद्यालय, 4 कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 1 खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, 08 अनुसंधान केन्द्र एवं 27 कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से संचालित कर रहा है। विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्तमान में लगभग 9000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें स्नातक पाठ्यक्रमों में 2763, स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रमों में 500 तथा शोध पाठ्यक्रमों (पी.एच.डी.) में 115 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहें हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् 52 फसलों की लगभग 162 प्रजातियों का विकास किया गया है एवं कृषि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 100 से अधिक तकनीकें विकसित की गई हैं।

अमेरिका सत्ता परिवर्तन और भारत चुनौतियों के समाधान की कोशिशें

शंकर अय्यर

अक्सर लोगों को परिस्थिति की गंभीरता को समझने के लिए आंकड़ों की जरूरत होती है। हाल ही में देश को बताया गया कि वर्ष 2024-25 में जीडीपी विकास दर घटकर 6.4 फीसदी रह सकती है। यह भी पता चला कि मुद्रास्फीति अधिक है, सार्वजनिक निवेश और औद्योगिक विकास बहुत कम है तथा खपत भी धीमी है। खपत को बढ़ावा देने के तरीकों पर खूब बहस हो रही है, जैसे आयकर दरों में कटौती का सुझाव दिया जा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ आंकड़ों पर ही गौर करेंगे, तो भ्रम पैदा होगा। सतत प्रयासों से ही समस्याएं दूर होंगी और विकास की राह भी खुलेगी। बगैर किसी क्रम के यहां दिए गए विचार इस संबंध में उपयोगी हो सकते हैं। मांग को नुकसान पहुंचाने वाला एक प्रमुख कारक खाद्य मुद्रास्फीति है, जो एक साल से अधिक समय से नष्ट होने वाली चीजों में सात फीसदी से ज्यादा है। भारत को इन चीजों के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड की आवश्यकता है, जैसा कि वर्गीज कुरियन ने दूध के लिए किया था। राष्ट्रीय ग्रिड के निर्माण से पैदावार में वृद्धि होगी, किसानों की आय में सुधार होगा, रोजगार में वृद्धि होगी और फसल कटाई के बाद होने वाली अन्न की बर्बादी पर अंकुश लगेगा, जो अनुमानित 25 प्रतिशत है। ग्रिड आगे और पीछे के लिंकेज को जोड़ेगा। शुरुआत के लिए, सरकार एक जिला, एक उत्पाद डाटाबेस का उपयोग कर सकती है और अमूल और मदर डेयरी खरीद मॉडल का उपयोग कर सकती है। सहकारी समितियों और निजी खिलाड़ियों द्वारा उत्पादन अनुबंधों में प्रवेश करने के बाद भंडारण की प्रक्रिया भी खरीद के बाद ही शुरू होगी। निश्चित रूप से, अनुबंधों के लिए नीतिगत बदलाव, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बढ़ाया गया ऋण और पंचायत स्तर पर कोल्ड चेन के वित्तपोषण की आवश्यकता होगी। औपचारिक ऋण तक पहुंच ने सूक्ष्म उद्यमियों को लगातार परेशान किया है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इस क्षेत्र में औपचारिक ऋण की पहुंच मात्र 20 फीसदी है। वित्त मामले के लिए संसद की स्थायी समिति ने भी पाया कि औपचारिक ऋण केवल 39 प्रतिशत छोटे उद्यमों को ही छू पाया है। सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण पाने के लिए निजी ऋणदाताओं को अत्यधिक ब्याज दरों का भुगतान करना पड़ता है, जैसा कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने संकेत दिया है। हालांकि बैंकों को उद्यम-पंजीकृत उद्यमियों को प्राथमिकता क्षेत्र के मानदंडों के तहत ऋण देने का निर्देश दिया गया है, पर लगता है कि पहुंच को या तो रोक दिया गया है या खारिज कर दिया गया है। सूक्ष्म उद्यमों को उद्यम क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है। इससे उद्यम पंजीकरण के आधार पर ऋण तक उनकी पहुंच हो सकती है। क्रेडिट सीमा को व्यवसाय के आकार और यूपीआई लेनदेन के आधार पर तय किया जा सकता है। भारत की विकास गाथा मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च से प्रेरित है। विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत अपनी जरूरत की अधिकांश ऊर्जा का आयात करता है, जिसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हालांकि, बुनियादी ढांचा एक अवसर प्रस्तुत करता है। भारत में करीब 1,50,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं; उच्च सौर विकिरण वाले राज्यों में करीब 70,000 किलोमीटर राजमार्ग हैं। नियमों के अनुसार, चार लेन वाले राजमार्गों को लगभग पांच मीटर (पहाड़ी क्षेत्रों में 2.5 मीटर) की चौड़ाई वाले डिवाइडर से बांटकर उस पर सौर पैनल लगाया जा सकता है। यह स्थान बिजली अपलोड करने और रखरखाव के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को क्षमता का नक्शा बनाने, पायलट परियोजनाएं आरंभ करने तथा सार्वजनिक और निजी निवेशकों से बोलियों के लिए तैयार स्थानों को पेश करने का निर्देश दे सकता है। जैसे-जैसे यह विचार आगे बढ़ेगा, यह प्रति किलोवाट-घंटे उपकरणों और ऊर्जा के मूल्य निर्धारण में बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं को गति देगा। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए फंडिंग में भारी वृद्धि की आवश्यकता है। स्टेट बैंक के चेयरमैन का अनुमान है कि 2036 तक आठ फीसदी ज्यादा की वृद्धि के लिए भारत को 1,094 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों का लाभ उठाना होगा। रणनीतिक विनिवेश के विचार को धन और शक्ति के संकेंद्रण की चिंताओं से चुनौती मिलती है। यह पक्षपातपूर्ण राजनीति से भी ग्रस्त होता है। निजीकरण के ढांचे से हटकर साझा सार्वजनिक स्वामित्व की ओर कदम बढ़ाना एक व्यवहार्य रास्ता है। विचार यह है कि सरकार की सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी को अमृत काल कोष में डाल दिया जाए, जो सिंगापुर की जीआईसी जैसी एक संप्रभु इकाई होगी।

न सुशासन, न रोजगार, सिर्फ फ्रीबीज की बौछार

कमलेश पांडे

राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावों के समय मतदाताओं के लिए एक से बढ़कर एक %फ्रीबीज% की जो बौछारें हो रही हैं, वह वोटर्स को %रिश्वत% नहीं तो और क्या है, इसे समझना जरूरी है! वहीं, जिन राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी वायदों के अनुपालन में कोताही बरती, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी स्पष्ट नहीं है! इसलिए वायदे करो और फिर मुकर जाओ या फिर आधे-अधूरे पूरे करो, कोई पूछने वाला नहीं है! तभी तो राजनीतिक दलों की बल्ले-बल्ले है। चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का शोर मचा हुआ है, इसलिए इस फ्रीबीज की चर्चा पुनः आवश्यक है, ताकि मतदाता जागरूक हो सकें।

कहने को तो दिल्ली को छोटा हिन्दुस्तान और दिल वालों का शहर कहा जाता है, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में यहां जितनी राजनीतिक दिलग्गी हुई, वह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और एनडीए हो या फिर राज्य में सत्तारूढ़ आप और इंडिया गठबंधन, जिससे कभी आप जुड़ती है तो कभी %तलाक% ले लेती है! और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो अपने नेतृत्व वाले गठबंधन या फिर अपने द्वारा समर्थित गठबंधन का अपनी सुविधा के अनुसार %गला मरोड़ने% में माहिर समझी जाती है, ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राजनीतिक किंतु-परन्तु की सारी हदें पार कर चुकी हैं।

चूंकि इन राजनीतिक दलों ने खुद के लिए कोई आदर्श राजनीतिक नियम और उसके निमित्त बाध्यकारी कानून नहीं बनाकर रखे हैं, या फिर नाममात्र का बनाए हुए हैं, जिसकी व्याख्या ये लोग अपने मनमुताबिक कर लेते हैं, इसलिए इनकी सारी राजनीतिक हरकतें जायज समझी जाती हैं। वहीं, इनको तोहफा या सजा बस जीत-हार के माध्यम से जनता जनार्दन ही देती आई है। यहां भी वह मतदाता दलित-महादलित, पिछड़ा-अत्यंत पिछड़ा, सवर्ण-गरीब सवर्ण, आदिवासी-अल्पसंख्यक, महिला-पुरूष, युवा-बुजुर्ग, किसान-मजदूर, कामगार या पूंजीपति आदि इतने खानों में विभाजित है कि उनकी फूट डालो और शासन करो की नीति अक्सर सफल होती आई है।

शायद इसलिए जनता, सरकार और सुशासन के मुद्दे गौण पड़ जाते हैं और फ्रीबीज की चर्चा घर-घर पहुंचकर चुनावी खेल कर देती है। ऐसे में सुलगता हुआ सवाल है कि सुशासन से लेकर रोजगार के मोर्चे पर विफल हो चुकीं जनतांत्रिक सरकारों के द्वारा जिस तरह से फ्रीबीज की घोषणाएं की जा रही हैं, क्या

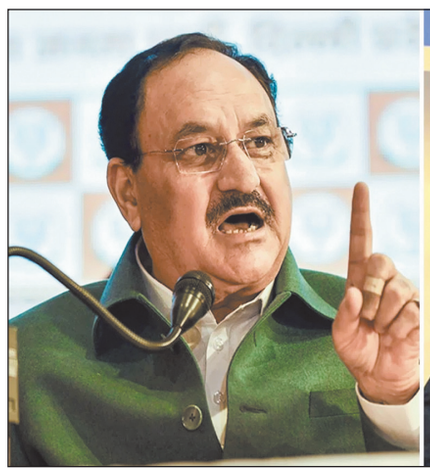

यह देश की आर्थिक व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था के लिहाज से उचित है या फिर अनुचित है? यदि अनुचित है तो इससे बचने का रास्ता क्या है?

देखा जाए तो कबीलाई युग से लोकतांत्रिक सरकार तक मनुष्य की पहली जरूरत शांति और सुरक्षा है, ताकि वह मेहनत करते हुए अपना जीवन निर्वाह कर सके और इस देश-दुनिया को बेहतर बनाने में अपने हिस्से का योगदान दे सके। हालांकि, ऐसे सुशासन की गारंटी न तो तब मिली थी और न अब मिली हुई है। शासक-प्रशासक बेहतर हो तो क्षणिक सुख-शांति संभव है, अन्यथा जलालत ही मानवीय सच है।

याद दिला दें कि एक जमाने में जो राजनीतिक दल शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में कटौती दर कटौती करते चले गए कि राजकोषीय घाटा को पाटना है! और अब उन्हीं के द्वारा जब फ्रीबीज की वकालत हो रही है तो इस सियासी तिकड़म को समझना भी दिलचस्प है। चाहे संसदीय चुनाव हो या विधान मंडलीय चुनाव, या फिर स्थानीय चुनाव, होने तो 5 साल में ही हैं। इसलिए जैसे तैसे चुनावी वायदे करके सरकार बना लो, इसी घुड़दौड़ में सभी राजनीतिक दल जूटे हुए हैं।

अब लोगों की दिलचस्पी न तो आजादी के तराने सुनने में है, न ही हिंदुत्व की माला जपने में। समाजवाद से लेकर वामपंथ तक अपने ही राजनीतिक हमाम में नंगे हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस विरोधी %सम्पूर्ण क्रांति% की सफलता-विफलता के लगभग चार दशक बाद हुई दूसरी कांग्रेस विरोधी %अन्ना हजारे क्रांति% की सफलता से उपजी आम आदमी पार्टी ने जो फ्रीबीज की सियासी लत लगाई और दिल्ली से पंजाब तक कांग्रेस-भाजपा का सफाया कर दी, उससे दोनों पार्टियों ने शुरुआती आलोचनाओं के बाद आप के सियासी एजेंडे को ही अपनाने में सफलता पाई। हिमाचल प्रदेश से कर्नाटक तक कांग्रेस की विजय और हरियाणा से उड़ीसा तक भाजपा की जीत इसी बात की साक्षी है।

यही वजह है कि भाजपा नीत एनडीए, आप नीत संभावित तीसरा मोर्चा और कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में एक-दूसरे को मात देने के लिए अपने-अपने फ्रीबीज के सियासी घोड़े खोल रखे हैं। वह भी तब, जब करदाताओं की ओर से इसकी खुलेआम आलोचना हो रही है। वहीं, आपने देखा-सुना होगा कि केंद्र सरकार की अटपटी नीतियों पर सर्वोच्च न्यायालय तक ने टिप्पणी की, कि आखिर 80 करोड़ लोगों को आप कबतक मुफ्त या फिर कम कीमत पर अनाज देंगे। ऐसे में उन्हें आप रोजगार क्यों नहीं दे देते! कोर्ट की यह टिप्पणी जायज है और प्रशासन यदि चाहे तो उसके लिए यह मुश्किल भी नहीं है।

वहीं, आम आदमी पार्टी ने अनुमन्य यूनिट तक फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री और किफायती शिक्षा व स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, लक्षित वर्गों को अलग-अलग नगद आर्थिक मदद आदि जैसी जो चुनावी-प्रशासनिक रवायतें शुरू की है, और अब उन्हीं की देखा-देखी कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों में भी इस नीतिगत मुद्दे पर आपाधापी मची हुई है, यह नीति एक नए आर्थिक और अर्थव्यवस्था के संकट को जन्म दे सकती है। इसलिए इसको हतोत्साहित करने के लिए मतदाताओं को ही आगे आना होगा, अन्यथा यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक कैंसर साबित होंगे। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये भी तो इसी बात की चुगली करते हैं।

आपने देखा-सुना होगा कि सरकार ने उद्योगपतियों के इतने के कर्जे माफ कर दिए, या फिर इतनी की सब्सिडी इन-इन धंधों/पेशों में दी जा रहीं हैं। इसी तरह से सरकार ने किसानों के इतने के कर्जे माफ कर दिए और इन-इन चीजों पर इतनी सब्सिडी दे रही है। इसी तरह से समाज के विभिन्न वर्गों को भी लुभाने के लिए सरकार कुछ न कुछ देकर दानी-दाता बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार सबको सुशासन क्यों नहीं दे रही है? सड़कों पर इंसान सुरक्षित क्यों नहीं है? चाहे खेती हो या कारोबार, चोरी और लूट की बढ़ती फितरत से उद्यमी व मेहनतकश वर्ग परेशान है। वहीं, डिजिटल धोखाधड़ी और प्रशासनिक तिकड़मों का तो कहना ही क्या है? बेहतर पुलिसिंग आज भी यक्ष प्रश्न है।

वहीं, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार और उसके पूंजीपति मित्रों का बढ़ता कब्जा, भूमि और मौद्रिक संसाधनों के असमान बंटवारे की नीति, समान मताधिकार से इतर विभिन्न कानूनी असमानताएं समाज और व्यवस्था को निरंतर खोखला करती जा रही हैं। इससे पूंजीपतियों की जमात, उनके शागिर्द, प्रशासनिक हुक्मरान और उसकी पूरी चेन, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की फौज और उनके करीबी लोग तो हर तरीके से मस्त हैं, लेकिन आमलोगों की फटेहाली पर तरस खाना स्वभाविक है। जिनके पास कुछ पूंजी-पगहा, मकान-दुकान या खेती योग्य जमीन या फिर छोटी-मोटी निजी या सरकारी नौकरी है, वह तो किसी तरह गुजर-बसर कर लेते हैं, लेकिन जो न शिक्षित हैं, न संसाधनों से लैस, उनकी बेचारगी देखते ही बनती है।

ऐसे में सबको समान शिक्षा और योग्यता के मुताबिक रोजगार देने की सरकारी नीति आखिर कब आकार लेगी, ज्वलंत प्रश्न है। वहीं, न तो सबके लिए जनस्वास्थ्य सुनिश्चित है और न ही सुविधाजनक परिवहन। गरीबी हटाओ और रोटी-कपड़ा-मकान का नारा भी टांय-टांय फिस्स हो चुका है। सबको शिक्षा-स्वास्थ्य-सम्मान की सामाजिक न्याय वाली बात भी पूंजीपतियों के एजेंडे की दासी बन चुकी है। यह सब इसलिए कि भले ही सरकार अपने नागरिकों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय समानताओं की बात करती है, लेकिन असमान कानूनों को गढ़कर वह ही सबसे ज्यादा सामाजिक विभेद भी पैदा कर रही है।

सवाल है कि उसका लोकतंत्र आखिर पूंजीपतियों का संरक्षक क्यों बना बैठा है। क्या फ्रीबीज का लॉलीपॉप थमाकर पूंजीपति सभी राष्ट्रीय संसाधनों पर काबिज हो जाएंगे, फिर उसके बाद लोगों को बाबाजी का ठुल्लू थमा देंगे, यही उनकी योजना है। यदि यही न्यू वर्ल्ड आर्डर है या फिर ग्लोबल पैटर्न तो फिर समाज के प्रबुद्ध वर्ग को सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि दलितों और पिछड़ों के लोकलुभावन वोटिंग पैटर्न के चक्कर में सबसे ज्यादा समाज का माध्यम वर्ग ही पिसेगा, यही नई त्रासदी है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

स्वामी दयानन्द ने जो वेदों के अर्थों का अनर्थ कर डाला है- इसका प्रधान कारण शैली कोन समझना ही है। आपने श्रनादि वेदों को भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए व्याकरण के शिकओं में जकड़ने की चेष्टा की है, इसलिए श्रापका वेदभाष्य ब्राह्मण, सूत्र और निरुक्तादि के सर्वथा विपरीत एवं उपहासास्पद बना हुआ है। कहीं रेल, कहीं तार, कहीं बिजली और कहीं हवाई जहाज गर्जे कि अदृष्ट-फलाधायक, अध्यात्म- ज्ञान के भण्डार को लुहारों और बढ़इयों (Carpenter) की शब्दकोष (Dictionary) बना छोड़ा है। यह सब अनर्थ वेदशैली को न जानने का ही परिणाम है।

हम इस विषय को अधिक लम्बायमान करना अनावश्यक समझते हैं। तत्त्व केवल इतना ही है, कि सर्वप्रथम पाठ्य-गन्थ की शैली का अनन करना चाहिए, तत्पश्चात् उसी शैली का अनुसरण करते हुए ग्रन्थ का तात्पर्य लगाने में प्रवृत्त होना चाहिए यह है ग्रन्थ समझने का तरीका! और ग्रन्थकार के हृदय तक पहुंचने का परिष्कृत मार्ग!! अत: इस अध्याय में हम पुराणों की शैली का निरूपण करते हैं।

शब्द-विचार : हम पीछे कह चुके हैं कि प्रत्येक शास्त्र में कुछ न कुछ पारिभाषिक एवं विशिष्ट शब्दों का प्राधान्य रहता है। पुराणों में भी ऐसे शब्दों की कमी नहीं है। यदि हम वर्णात्मक घट-पटादिक शब्दों का अपौरुषेय और पौरुषेय दृष्टि से विश्लेषण करना चाहें तो समस्त शब्दराशि दो भागों में विभक्त हो जाती है। (1) प्रथम विभाग में उन सब शब्दों का समावेश होगा जो कि वे में प्रयुक्त हुये हैं और चिरंतन महर्षियों ने जिनको अनादि अपौरुषेय एवं ईश्वरीय रूप में स्वीकार किया है। (2) दूसरे विभाग में बाकी सत्र शब्दों को गिना जा सकता है। इस प्रकार हम उक्त दोनों विभागों को क्रमश: वैदिक और लौकिक कह सकते हैं।

क्रमश: ...

आजाद हिंद सेना के संस्थापक थे रास बिहारी बोस

बाल मुकुन्द ओझा

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रासबिहारी बोस का नाम आदर पूर्वक लिया जाता है। रासबिहारी बोस भारत के एक महान क्रान्तिकारी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध गदर षड्यंत्र एवं आजाद हिन्द फौज के संगठन का कार्य किया। इन्होंने न केवल भारत में कई क्रान्तिकारी गतिविधियों का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, अपितु विदेश में रहकर भी वह भारत को स्वतन्त्रता दिलाने के प्रयास में आजीवन लगे रहे। दिल्ली में तत्कालीन वायसराय लार्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने, गदर की साजिश रचने और बाद में जापान जाकर इंडियन इंडिपेंडेस लीग और आजाद हिंद फौज की स्थापना करने में रासबिहारी बोस की महत्वपूर्ण

भूमिका रही। यद्यपि देश को स्वतन्त्र कराने के लिये किये गये उनके ये प्रयास सफल नहीं हो पाये, तथापि स्वतन्त्रता संग्राम में उनकी भूमिका का महत्व बहुत ऊँचा है।

रासबिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को बंगाल में बर्धमान जिले के सुबालदह गाँव में हुआ था। प्रथम महायुद्ध में सशस्त्र क्रांति की जो योजना बनाई गई थी, वह रासबिहारी बोस के ही नेतृत्व में निर्मित हुई थी। सन् 1912 ई. में वाइसराय लार्ड हार्डिंग पर रासबिहारी बोस ने ही बम फेंका था। प्रख्यात वकील और शिक्षाविद रास बिहारी बोस क्रांतिकारी तो थे ही, सर्वप्रथम आजाद हिन्द फौज के निर्माता भी थे। रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज के आधार स्तंभ थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर उसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। बीसवीं सदी के शुरूआती दशकों में जितने बड़े क्रांतिकारी षड्यंत्र हुए थे, उन सबके सूत्रधारों में शामिल थे रास बिहारी बोस। गदर रिवोल्यूशन से लेकर अलीपुर बम कांड केस तक, गर्वनर जनरल हॉर्डिंग की हत्या की प्लानिंग से लेकर मशहूर क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी के उत्तर भारत में विस्तार तक। महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस का नाम हमेशा आदर के साथ लिया जाता रहेगा। उन्होंने न केवल देश में कई क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि विदेश में रहकर भी वह देश को आजादी दिलाने के प्रयास में आजीवन लगे रहे।

सर्वप्रथम आजाद हिन्द फौज के निर्माता रासबिहारी बोस उन लोगों में से थे जो देश से बाहर जाकर विदेशी राष्ट्रों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण तैयार कर भारत की मुक्ति का रास्ता निकालने की सोचते रहे, सभी भारतीयों को आह्वान कर भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। रास बिहारी बोस ने 12 मई 1915 को कोलकाता छोड़ा। वे राजा पी.एन.टी. टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर के दूर के रिश्तेदार बनकर जापान गए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रवींद्रनाथ टैगोर इस छद्म रूप को जानते थे।

दूसरा महायुद्ध समाप्त होने से पूर्व, 21 जनवरी 1945 को टोकियो में रासबिहारी बोस की मृत्यु हो गयी। जापानी सरकार ने एक विदेशी को दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि से उनका सम्मान किया।

हमास-इस्राइल युद्ध विराम सही कदम है

डॉ. धनंजय त्रिपाठी

इस्राइल और हमास के बीच बीते लगभग 15 महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए हाल ही में दोनों पक्षों द्वारा सहमति जताने का स्वागत किया जाना चाहिए। यह एक अच्छा प्रस्ताव है, क्योंकि वहां पर बहुत दिनों से दोनों पक्षों के बीच लड़ाई चल रही थी और इसमें आम जनता ही ज्यादा हताहत हो रही थी। उसे ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। इस हिसाब से देखा जाए, तो गाजा में युद्ध रोकने का यह एक अच्छा प्रयास है। अच्छा प्रयास इसलिए भी, क्योंकि तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठन इस युद्ध को रोकने में विफल रहे हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था भी। तो, युद्ध विराम पर दोनों पक्षों द्वारा सहमति जताना एक बड़ी चीज है, एक सकारात्मक कदम है।

इस प्रस्ताव को लेकर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वह इसमें मौजूद शर्तें हैं। इन शर्तों में कहा गया है कि प्रस्ताव को तीन चरणों में लागू किया जायेगा। इसके पहले चरण के तहत, अक्तूबर 2023 में हमास द्वारा हमला करने के बाद जिन इस्राइली नागरिकों को बंधक बनाया गया था, उन इस्राइली नागरिकों को छोड़ने की बात कही गयी है। इसमें हमास की तरफ से कहा गया है कि वह पहले 33 इस्राइली बंधकों को रिहा करेगा। इस्राइल ने भी स्वीकार किया है कि वह हजार के करीब फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करेगा। विदित हो कि अभी भी करीब 90 इस्राइली नागरिक हमास के कब्जे में ही हैं। इस्राइल की लाख कोशिशों के बावजूद वे छूट नहीं पाये हैं। 42 दिनों के पहले चरण में बंधकों को छोड़ा जायेगा, युद्ध विराम होगा और इस्राइली सेना, जो फिलिस्तीनी

आबादी वाले बहुत से क्षेत्रों में मौजूद हैं, उनकी वहां से वापसी होगी और जो विस्थापित फिलिस्तीनी हैं, वो इन जगहों पर वापस लौटेंगे। दूसरे चरण में यह होगा कि हमास और इस्राइल, दोनों ही एक-दूसरे के बाकी बचे हुए बंधकों को रिहा करेंगे। अब बात तीसरे चरण की। तो, तीसरे चरण में गाजा में पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है, क्योंकि युद्ध के दौरान गाजा में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भले ही प्रस्ताव में कहा गया है कि इस्राइल फिलिस्तीनी आबादी वाले क्षेत्र से अपनी सेना हटा लेगा, पर इस्राइल का कहना है कि वह पूरी तरीके से इन क्षेत्रों से अपनी सेना नहीं हटायेगा।

ऊपर-ऊपर यदि देखा जाए, तो हमें लगता है कि हमास-इस्राइल द्वारा शांति प्रस्ताव को मान लेने से युद्ध विराम हो जायेगा और इस क्षेत्र में शांति आ जायेगी। इसी कारण इस प्रस्ताव को दोनों पक्षों ने माना है, परंतु यदि आप इसके तह में जायेंगे, तो पायेंगे कि इस्राइल को जो भी करना था, विशेषकर हमास की क्षमता को नुकसान पहुंचाना, तो वह बहुत हद तक ऐसा करने में सफल रहा है। हालांकि हमास पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, पर उसके संगठन को बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। इसके साथ ही, लेबनान में हिज्बुल्लाह के संगठन को भी इस्राइल ने बड़ी क्षति पहुंचायी है। तो, जो युद्ध विराम हो रहा है, उससे यह समझिए कि इस्राइल के जो प्राथमिक उद्देश्य थे, उसे उसने कमोबेश पा लिया है। मेरी समझ से उसके युद्ध विराम के लिए तैयार होने का एक अन्य कारण उसके नागरिकों का हमास के कब्जे में होना है। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि हमास के कब्जे में जो अभी भी 90 इस्राइली नागरिक हैं, उनमें से सभी जीवित हैं या कुछ मारे जा चुके हैं। बहरहाल, युद्ध विराम के प्रस्ताव को मानने से इस्राइली अपने नागरिकों को हमास के कब्जे से छुड़ाने में सफल हो जायेगा।

जहां तक युद्ध विराम से शांति व स्थिरता की बात है, तो पहले दिन से ही यह बात लोगों के मन में थी कि इस समस्या का समाधान कभी भी केवल युद्ध नहीं हो सकता है, बातचीत, समझौता तो कभी न कभी करना ही होगा। यह बात भी सच है कि अभी जो युद्ध विराम के लिए समझौते हो रहे हैं, वहां पर हमास काफी कमजोर स्थिति में है और इस्राइल काफी मजबूत स्थिति में है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इससे अरब देशों पर लगातार जो उनकी जनता की ओर से दबाव पड़ रहा था कि वह इस युद्ध में हस्तक्षेप करें, इस्राइल के साथ सख्ती से पेश आएं और ऐसा करने से वे बच रहे थे, उससे अरब देशों को भी थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि युद्ध रुकने के बाद यह दबाव उनके ऊपर से हट जायेगा। चाहे वह सऊदी अरब हो या खाड़ी के अन्य देश हों।

तीसरी बात, विश्वभर में इस युद्ध को लेकर जो वाद-विवाद हो रहा था, गहमा-गहमी चल रही थी, विशेषकर पश्चिम के विश्वविद्यालयों के भीतर इसे लेकर जो प्रदर्शन चल रहे थे, वहां भी अब थोड़ी शांति आयेगी। विश्वभर में इस युद्ध को लेकर जो एक चिंता बनी हुई थी, वह कम होगी और यह जरूरी भी था, क्योंकि यह युद्ध लगभग पंद्रह महीने तो चल ही चुका था। यह युद्ध यदि और लंबा खिंचता, तो अंतरराष्ट्रीय समुदायों के बीच का विभाजन और गहरा जाता। उस हिसाब से भी यह एक अच्छी पहल है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे फिलिस्तीनी नागरिक, जो पूरी तरीके से विस्थापित हो गये थे, जो रोज-रोज संघर्षों से जूझ रहे थे, जिनके पास न पर्याप्त भोजन था, न दवाइयां थीं, उनके परिवार की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गयी थी, इस युद्ध विराम से उनको सबसे अधिक राहत व शांति मिलेगी। एक, वे अपने घर लौट पायेंगे और उनके जीवन में जो अस्थिरता आ गयी थी, पुनर्निर्माण होने से उनमें स्थिरता आयेगी। दूसरी ओर इस्राइल के भीतर भी जो अनिश्चितता बनी हुई थी, वह दूर होगी। इस्राइली नागरिकों के जीवन में भी शांति आयेगी, क्योंकि वे भी युद्ध शुरू होने के बाद से असुरक्षा के साये में जी रहे थे। उनके जीवन पर भी निरंतर खतरा मंडरा रहा था। अंत में, इस युद्ध के दौरान कई बार ऐसी स्थिति भी बनी जहां लगा कि ईरान और इस्राइल के बीच युद्ध न छिड़ जाए। दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका के कारण पूरी दुनिया में तनाव बढ़ गया था, सभी को लगता था कि ऐसी स्थिति में तेल की कीमतों का क्या होगा। तो, कहीं न कहीं पूरे विश्व में इस युद्ध को लेकर अस्थिरता और असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। युद्ध विराम से इन सब पर विराम लगेगा। ईरान और इस्राइल के बीच जो गंभीर तनातनी चल रही थी, दो बार तो युद्ध की स्थिति बन भी गयी थी, उसे लेकर पूरे पश्चिम एशिया के भीतर बड़ी चिंताएं थीं। वह सब चिंताएं समाप्त हो जायेंगी और पूरा विश्व इससे राहत की सांस लेगा।

आज का इतिहास

1945 फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट चौथी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने।
1959 यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की गई।
1960 मरकारी अंतरिक्षयान के लॉन्च एस्केप सिस्टम, लिटिल जो 1बी ने प्रायोगिक उड़ान भरी।
1963 हिन्दी साहित्य के जाने माने उपन्यासकार, कहानीकार, सम्पादक और पत्रकार शिवपूजन सहाय का निधन हुआ।
1963 कांगो-लोपोल्डविले और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप में अराजकता की अवधि के बाद, कटंगा की गोपनीयता समाप्त हो गई।
1968 वियतनाम युद्ध-वियतनाम पीपुल्स आर्मी ने खीर सैन बैटल की शुरुआत करते हुए क्वांग ट्राई प्रोविंस, दक्षिण वियतनाम में अमेरिकी मरीन की चौकी पर खेले सन कॉम्बैटबेस पर हमला किया।
1968 शीत युद्ध-ए बी -52 बमवर्षक चार परमाणु हथियार ले जा रहा था, थ्यूल एयर बेस, ग्रीनलैंड के पास समुद्री बर्फ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे व्यापक रेडियोधर्मी संदूषण हुआ।
1973 डेनमार्क में कम्युनिस्ट लीग की स्थापना की गई।
1976 कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट ने लंदन, पेरिस, बहरीन और रियो डी जनेरियो के लिए निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानें शुरू कीं।
1980 अमेरिका के राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने मॉस्को ओलंपिक के बहिष्कार की घोषणा की।
1986 मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सम्मान में पहली बार संघीय छुट्टी हुई।
1994 लोरेन बॉबिट को अपने पति जॉन को मारने के आरोपों पर पागलपन के कारण दोषी नहीं पाया गया।
1996 इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास यात्रियों से भरी नाव डूबने से लगभग 340 लोगों की मौत।
1996 रूडी गैलिंडो ने अमेरिकी पुरुष चैंपियनशिप जीती।
1996 53 वें गोल्डन ग्लोब्स: एलीट मेल गिब्सन, निकोल किडमैन और जॉन ट्रावोल्टा हैं।
2008 अलास्का में आंखों की भाषा मैरी स्मिथ जोन्स के बाद विलुप्त हो गई, भाषा का अंतिम मूल वक्ता, मृत्यु हो गई, एक घटना जो भाषा विलुप्त होने के खिलाफ लड़ाई में एक प्रतीक बन गई।

युद्ध विराम समझौते का ईमानदारी से पालन जरूरी

ललित गर्ग

यह शांतिपूर्ण विश्व संरचना के लिये सुखद ही है कि करीब डेढ़ वर्ष से जारी इस्राइल-हमास संघर्ष खत्म करने के लिये युद्धविराम पर सहमति बन गई है। लेकिन इस एवं ऐसे युद्धों ने ऐसे अनेक ज्वलंत प्रश्न खड़े किये हैं कि जब युद्ध की अन्तिम निष्पत्ति टेबल पर बैठकर समझौता करना ही है तो यह युद्ध के प्रारंभ में ही क्यों नहीं हो जाता? युद्ध भीषणतम तबाही, असंख्य लोगों की जनहानि एवं सर्वनाश का कारण बनता है तो ऐसी तबाही होने ही क्यों दी जाये? खेर देर आये दुरस्त आये, इजराइल और हमास ने बुधवार को युद्ध विराम समझौते के पहले मसौदे पर सहमति जताई, जो संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा एवं अहम कदम है। अन्य बातों के अलावा, 60-दिवसीय युद्ध विराम प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बंधकों को रिहा करना, सहायता बढ़ाना, नष्ट हो चुके फिलिस्तीन का पुनर्निर्माण करना और हमलों को रोकना शामिल होगा। डेढ़ साल से अधिक समय के युद्ध के बाद, युद्ध विराम फिलिस्तीन के लोगों तथा हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के लिए बहुत जरूरी राहत है। इसी तरह रूस एवं यूक्रेन के बीच लम्बे समय से चल रहा युद्ध भी समाप्त हो, यह शांतिपूर्ण उन्नत विश्व संरचना के लिये नितांत अपेक्षित है। क्योंकि ऐसे युद्धों से युद्धरत देश ही नहीं, समूची दुनिया पीड़ित, परेशान एवं प्रभावित होती है। इस तरह युद्धरत बने रहना खुद में एक असाधारण और अति-संवेदनशील मामला है, जो समूची दुनिया को विनाश एवं विध्वंस की ओर धकेलने देता है। ऐसे युद्धों में वैसे तो जीत किसी की भी नहीं होती, फिर भी इन युद्धों का होना विजेता एवं विजित दोनों ही राष्ट्रों को सदियों तक पीछे धकेल देता, इससे भौतिक हानि के अतिरिक्त मानवता के अपाहिज और विकलांग होने के साथ बड़ी जनहानि का भी बड़ा कारण बनता है।

इस्राइल-हमास में पिछले डेढ़ साल से चल रहे युद्ध के विराम को एक अहम कामयाबी माना जा रहा है। भले ही इस समझौते के लिये अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बीच संघर्ष समाप्ति का श्रेय लेने की होड़ हो, लेकिन गाजा के लोग जिस मानवीय त्रासदी से जूझ रहे थे, उन्हें जरूर इससे बड़ी राहत मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र के तमाम प्रयासों व मध्यपूर्व के इस्लामिक देशों एवं भारत की बार-बार की गई पहल के बावजूद अब तक शांति वार्ता सिरे न चढ़ सकी थी। जिसकी कीमत करीब पचास हजार लोगों ने अपनी जान देकर चुकायी। इस युद्ध से गाजा के विभिन्न क्षेत्रों में जो तबाही हुई है, उससे उबरने में दशकों लग सकते हैं।

निस्संदेह, इस्राइल व हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति होना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक समझौता यथार्थ में लागू होता न नजर आए, तब कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। संघर्ष में वास्तव में हमास के कितने लड़ाके मारे गए यह कहना कठिन है, लेकिन बड़ी संख्या में बच्चों-महिलाओं ने युद्ध में जान गवांई। एक अनुमान के अनुसार गाजा संघर्ष में उपजी मानवीय त्रासदी में करीब बीस लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इस्राइली हमलों में अस्पताल-स्कूल भी निशाना बने, जिन्हें शरणार्थियों की सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है। इस्राइल पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में युद्ध अपराध तक के आरोप लगाए गए। बहरहाल, जब लंबे समय के बाद शांति की स्थितियां बन रही हैं तो विश्व समुदाय, शक्तिशाली राष्ट्रों व संयुक्त राष्ट्र का दायित्व बनता है कि समझौते की शर्तों

को साफ नियत एवं नीति से क्रियान्वित किया जाये। ताकि मध्यपूर्व में स्थायी शांति एवं अमनचैन की राह मजबूत हो सके। निश्चित रूप से युद्ध शांति का विकल्प नहीं हो सकता। इस संघर्ष की शुरुआत भले हमास ने की हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत उन लोगों ने चुकाई, जो इसके लिये जिम्मेदार नहीं थे।

युद्ध के आघात से युद्धरत देशों के साथ समूची दुनिया प्रभावित हुई है। युद्ध के आघात से तात्पर्य युद्ध के दौरान होने वाली दर्दनाक घटनाओं के परिणामस्वरूप व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक संकट और शारीरिक-भावनात्मक पीड़ा से है, जैसे कि हिंसा का शिकार होना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, या संघर्ष के कारण प्रियजनों को खोना। युद्ध सामाजिक विश्वास को तोड़ता है, सामाजिक सामंजस्य को कम करता है और सामाजिक एवं राष्ट्रीय पूंजी को नुकसान पहुंचाता है। सशस्त्र संघर्ष के बाद, समाज उपसमूहों में गहराई से विभाजित हो जाता है जो युद्ध विराम के समझौते के बावजूद बाद के दौर में एक दूसरे से डरते हैं और नफरत करते हैं और लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार रहते हैं। युद्ध के आघात से पीड़ित लोगों में अक्सर दूसरे पक्ष के साथ मेल-मिलाप करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने की इच्छा कम हो जाती है। कमजोर नागरिक समाज और कम सरकारी क्षमताएं लोगों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ बना सकती हैं और राज्य के बिगाड़ने वालों या राजनीतिक विरोधियों द्वारा आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। यह स्थिति अक्सर हिंसा के निरंतर चक्रों के लिए मंच तैयार करती है। हालांकि, अक्तूबर, 2023 में हमास के हमले से आहत इस्राइल कई मोर्चों पर लगातार युद्ध से थक चुका है, लेकिन अभी भी अरब जगत उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। ऐसी आशंका इसीलिए भी है कि कई बार बातचीत अंतिम दौर पर पहुंचते-पहुंचते पटरी से उतरती गई है। बात और घात लगातार चलते रहे हैं। अब भविष्य में देखना होगा कि दोनों पक्ष समझौते के अमल के प्रति कितनी ईमानदारी से प्रतिबद्ध नजर आते हैं। हालांकि, अपने बंधकों की जल्द रिहाई को लेकर इस्राइल के विपक्षी राजनीतिक दलों व मंत्रिमंडल में भी मतभेद उभर रहे हैं, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बाद थक चुकी इस्राइली सेना को भी राहत देने की मांग की जाती रही है। बहरहाल, युद्ध विराम के प्रश्न पर इस्राइल व हमास के बीच सहमति से शांति की उम्मीदें प्रबल हुई हैं। जहां एक ओर अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन व नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौते के लिए श्रेय ले रहे हैं, वहीं ईरान इसे फलस्तीनी प्रतिरोध की जीत बता रहा है। अभी गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया जाना है। दरअसल, सात अक्तूबर 2023 को हमास के क्रूर हमलों में इस्राइल के बारह सौ लोग मारे गए थे और करीब ढाई सौ लोगों को हमास के लड़ाके सौदेबाजी के लिये बंधक बनाकर ले गए थे। साफ था कि इस अपमानजक घटना का इस्राइल प्रतिशोध लेगा, लेकिन संघर्ष करीब डेढ़ वर्ष तक चलेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हालांकि, कुछ इस्राइली बंधक रिहा किए गए, कुछ युद्ध के बीच मारे गए, लेकिन बचे बंधकों की रिहाई का भारी दबाव नेतन्याहू सरकार पर लगातार बना रहा। संघर्ष में वास्तव में हमास के कितने लड़ाके मारे गए यह कहना कठिन है, लेकिन बड़ी संख्या में बच्चों-महिलाओं ने युद्ध में जान गवांई। एक अनुमान के अनुसार गाजा संघर्ष में उपजी मानवीय त्रासदी में करीब बीस लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इस्राइली हमलों में अस्पताल-स्कूल भी निशाना बने, जिन्हें शरणार्थियों की सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है। इस्राइल पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में युद्ध अपराध तक के आरोप लगाए गए। निश्चित रूप से युद्ध शांति का विकल्प नहीं हो सकता। हालांकि, इस बात को लेकर शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इस समझौते से फिलस्तीनी संकट का स्थायी समाधान हो सकेगा। इस युद्ध मसले का हल कूटनीति और आपसी बातचीत से ही निकालने के प्रयास किये जाने की आवश्यकता भारत लगातार व्यक्त करता रहा है। युद्ध का अंधेरा मिटाने, शांति का उजला करने एवं अहिंसा-सहजीवन की कामना ही भारत का लक्ष्य रहा है। इसीलिये भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार युद्ध विराम की कोशिश करते हुए दोनों ही देशों को दिशा-दर्शन देते रहे हैं। इसी तरह रूस एवं यूक्रेन में भी युद्ध-विराम की अपेक्षा है। बड़े शक्तिसम्पन्न राष्ट्रों को इस युद्ध को विराम देने के प्रयास करने चाहिए। जब तक रूस के अहंकार का विसर्जन नहीं होता तब तक युद्ध की संभावनाएं मैदानों में, समुद्रों में, आकाश में तैरती रहेगी।

त्रिकोणीय होने से दिलचस्प दिल्ली चुनाव?

राजकुमार सिंह

एक दशक बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बनाने का श्रेय उस दल को है, जिसका पिछले दो चुनावों में खाता नहीं खुल पाया। पिछले दो चुनाव में एकतरफा जीती आम आदमी पार्टी (आप) को इस बार बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर इसलिए भी लगाना पड़ रहा है कि लगभग छह महीने पहले लोकसभा चुनाव मिल कर लड़ी कांग्रेस ने भी उसके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। यह अलग बात है कि पिछले

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को साढ़े चार प्रतिशत से भी कम वोट मिले थे। दोस्ती के अचानक फिर से दुश्मनी में बदल जाने के पीछे की असली कहानी तो कांग्रेस और आप का आलाकमान ही बेहतर जानता होगा, लेकिन दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। स्थानीय नेता तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही एक-दूसरे पर निशाना साधने में जुट गए थे। लेकिन अब इसमें आलाकमान की भी 'एंट्री' हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत सीलमपुर में रैली से करते हुए सीधा आरोप लगाया कि आप के संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह झूठे वायदे करते हैं। केजरीवाल ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। केजरीवाल की टिप्पणी थी- वह कांग्रेस बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मैं देश बचाने की। केजरीवाल को मोदी की तरह ही झूठे वायदों के लिए कठघरे में खड़ा करने से ऐसा लग सकता है कि कांग्रेस अपने दोनों विरोधी दलों पर समान रूप से हमला कर रही है, लेकिन असल में उसके निशाने पर आप ज्यादा है। शराब नीति घोटाले की शिकायत तो पुरानी हो गई। हाल ही में आप की महिला सम्मान योजना की शिकायत भी कांग्रेस ने ही उपराज्यपाल से की। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से केजरीवाल के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने पंजाब पुलिस द्वारा कांग्रेस उम्मीदवारों की जासूसी तथा चुनाव के लिए पंजाब से दिल्ली कैश लाए जाने की शिकायत भी उपराज्यपाल से की। जाहिर है, जांच शुरू हो चुकी है। कथित शीशमहल के मुद्दे पर भी कांग्रेस, भाजपा से कम आक्रामक नहीं है। कांग्रेस इस बार आप के प्रमुख नेताओं की जबर्दस्त चुनावी घेराबंदी भी कर रही है। खास बात यह भी कि कांग्रेस का फोकस उन दो दर्जन सीटों पर ज्यादा है, जो झुग्गी-झोपड़ी और अल्पसंख्यक बहुल हैं। गरीब, दलित और अल्पसंख्यक दिल्ली में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहे, लेकिन 2013 में बनी आप धीरे-धीरे उन्हें अपने पाले में ले गई।

सत्ता की बैसाखी पर टिके होने से बदल जाते हैं नेताओं के सुर

योगेंद्र योगी

बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलित प्रदेश के युवाओं की मांग पर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी आश्चर्यजनक नहीं है। दरअसल भाजपा न सिर्फ बिहार नीतिश सरकार में शामिल है, बल्कि केंद्र में भी उसी की बैसाखियों पर टिकी है। ऐसे में मुद्दा जनहित का हो या न हो, इससे भाजपा को फर्क नहीं पड़ता। इससे पार्टी के उसूलों पर भी आंच नहीं आती। इसी भाजपा ने राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ पेपर लीक प्रकरणों में विरोध प्रदर्शनों में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी। यह दोहरा चरित्र अकेले भाजपा का हो ऐसा नहीं है। जिस प्रदेश या केंद्र में जिस भी दल की सरकार होती है, वहां की सत्तारुढ़ पार्टी का रवैया ऐसा ही होता है। केंद्र में कांग्रेस शासन के दौरान सहयोगी दलों के घपले-घोटाले इसका प्रमाण रहे हैं। सत्ता के लिए गठबंधन की मजबूरी से ऐसा करना देश की राजनीति का चरित्र बन गया है। सत्ता में होने पर पार्टी को कुछ गलत नजर नहीं आता और विपक्ष में आते ही मुद्दे और तरीके बदल जाते हैं।

बिहार में 13 दिसंबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दिन से ही अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर इसे रद्द करके फिर से कराने की मांग की। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर छात्रों को पेपर देरी से मिला था और पेपर की सील पहले से खुली हुई थी। छात्र प्रदर्शनकारियों के पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल ने छात्रों और उनके संगठनों के आक्रोश को और बढ़ा दिया। बिहार की तरह राजस्थान भी कांग्रेस शासन के दौरान पेपर लीक प्रकरणों के कारण सुर्खियों में रहा है। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुई प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आए। सब इंस्पेक्टर भर्ती, सीएचओ भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती सहित कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने के खुलासे हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से व्याख्याता भर्ती 2022 की परीक्षा का पेपर लीक

होने का मामला सामने आया। पेपर लीक मामले में उलझी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर प्रदेश के लाखों युवाओं में हर ताजा अपडेट का इंतजार है। पेपर लीक और डमी अभ्यर्थियों के जरिए सैंकड़ों युवाओं ने नौकरी हासिल कर ली थी। इस मामले की जांच करने वाली एसओजी ने भी व्यापक स्तर पर पेपर लीक होना माना और इस परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश पुलिस मुख्यालय को भेजी थी। पुलिस मुख्यालय और मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने भी परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने इस भर्ती परीक्षा को अभी तक रद्द नहीं किया।

राज्य सरकार ने एसआई भर्ती 2021 में चयनित सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों के आगामी प्रशिक्षण पर रोक लगा दी। सरकार ने यह निर्णय राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश के बाद लिया। एक साल की लंबी एक्सरसाइज में अभी तक 50 सब इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं। आरपीएससी के सदस्य पकड़े गए। आश्चर्य की बात यह है कि राजस्थान में भाजपा सरकार केही एक केबीनेट मंत्री अपनी ही सरकार के फैसलों पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठा रहे हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सत्तारुढ़ भाजपा अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं कर सकी। अनुशासित माने जानी वाली भाजपा की मजबूरी है कि मीणा के खिलाफ पार्टी और सरकार की लाइन से अलग हट कर चलने को लेकर कार्रवाई नहीं कर सकी। इसमें भाजपा को मीणा के साथ जुड़े मीणा वोट बैंक के खिसकने का डर है। सत्ता के लिए राजनीतिक दल किस हद तक उसूलों को ताक पर रख देते हैं, मीणा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना इसका उदाहरण है। मीणा मंत्री पद से इस्तीफा तक दे चुकें हैं, हालांकि उन्होंने इस्तीफा लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर अपनी जिम्मेदारी मानते हुए दिया था। पार्टी ने अनुसूचित जाति में कोई गलत संदेश नहीं जाए, इसलिए मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। वोट बैंक के लिए समझौते की ऐसी अनोखी मिसाल देश में शायद ही कहीं देखने को मिले, जहां एक नेता के मंत्रीपद से इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि उसकी पार्टी विरोधी कार्रवाई झेलने को भी पार्टी मजबूर है। दरअसल ऐसे सार्वजनिक विवादित मुद्दों पर किसी भी सरकार के लिए फैसला लेना आसान नहीं होता। सरकारें एक तरफ जहां रोजगार देने के लिए अपनी छवि सुधारने में लगी होती हैं, वहीं दूसरी तरफ फिर से परीक्षा करवाने की कवायद खर्चीली और देरी करने वाली होती है। राज्यों में सत्तारुढ़ पार्टी के सामने समस्या यह भी होती है कि पेपर लीक होने से चुनिंदा लोगों को हुए फायदे के कारण परीक्षा रद्द करवाने से हजारों-लाखों अभ्यर्थियों के हितों का नुकसान नहीं किया जा सकता। ऐसे में सत्तारुढ़ दलों को दोनों तरफ से युवाओं की नाराजगी का खतरा होता है। यदि पेपर निरस्त करा दिया तो योग्यता सूची में आए अभ्यर्थियों की नाराजगी और नहीं कराया तो प्रदर्शनाकारियों की।

ऐसे हालात का विपक्षी दल फायदा उठाने से नहीं चूकते, जैसा कि बिहार के मामले में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने किया। सांसद यादव को बिहार प्रशासनिक सेवा आयोग से नाराज प्रदर्शनकारी युवाओं की सहानुभूति का फायदा मिल गया। ठीक यही स्थिति राजस्थान में मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के साथ है। यहां सत्तारुढ़ पार्टी भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और काबीना मंत्री मीणा अपनी ही सरकार और पार्टी को आईना दिखाने में लगे हुए हैं। इसके पीछे भी वोट बैंक की राजनीति है। मीणा ने पेपर लीक मामलों में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की नाक में दम कर दिया था। कांग्रेस के राजस्थान से सत्ता गंवाने का एक बड़ा कारण पेपर लीक मामले भी रहे हैं। यह निश्चित है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के राज्यों में होने वाले संचालन को सौ प्रतिशत चाक-चौबंद करना आसान नहीं है। कोई भी चूक और मिलीभगत पेपर लीक करवा सकती है। राजनीतिक दलों को रोटी सेकने के लिए ऐसे ही मौकों का इंतजार रहता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा, जब तक राजनीतिक दल मिल बैठकर किसी नीति पर कायम नहीं होते। तब तक न सिर्फ युवाओं के हितों पर कुठाराघात होता रहेगा, बल्कि सरकारी संसाधन और धन का भी नुकसान होता रहेगा।

आम आदमी पार्टी की संजीवनी योजना क्या है?

कमलेश पांडे

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दृष्टिगत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है, जिसे उन्होंने संजीवनी योजना का नाम दिया है। इस योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत होने वाले इलाज पर कोई खर्च सीमा नहीं होगी। इसके अलावा, लाभुकों के इलाज के लिए आय सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। इससे साफ है कि इस नई प्रस्तावित योजना के तहत इलाज फ्री, दवाई फ्री, सबकुछ फ्री किया जाएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को फायदा मिल सके।

हालांकि, यह कोई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी %आप% की तरफ से किया गया एक चुनावी वायदा है, जिसे वह चौथी बार सत्ता में आते ही सरकारी अमलीजामा पहनाएगी। दिल्ली प्रशासन ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले स्थानीय बुजुर्गों के लिए %संजीवनी योजना% नामक बुजुर्ग स्वास्थ्य योजना की घोषणा की, जो दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा चुनावी वादा है। इस योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए आय की भी कोई सीमा नहीं रखी गई है। हां, बुजुर्ग व्यक्ति दिल्ली के मूल निवासी हों, यह अनिवार्य बना दिया गया है। वहीं, इस योजना को लेकर आपके मन में भी तरह-तरह के सवाल पैदा हो रहे होंगे जिनका जवाब यहां देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप रणनीतिकारों से पूछताछ पर आधारित है। खासकर यह कि इस योजना के तहत इलाज पाने के लिए क्या-क्या करना होगा और किन-किन लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से-

आप की संजीवनी योजना एक मेडिकल स्कीम है, जिसे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सभी वरिष्ठ

नागरिकों के लिए लॉन्च किया है। यह योजना 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त इलाज प्रदान करेगी। कहने का तातपर्य यह कि इस योजना के तहत 60 साल और उससे ऊपर की उम्र के लोग अपना इलाज करा सकते हैं। वहीं, इस योजना में इनकम को लेकर कोई विशेष नियम नहीं बनाया गया है, ताकि सभी वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी आय सीमा के ही मुफ्त इलाज मिलेगा।

जहां तक इस योजना का लाभ प्राप्त करने की बात है तो इसके लिए आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सम्पर्क करना होगा, क्योंकि वही लोग घर-घर जाकर इस योजना के लिए पंजीकरण कर रहे हैं। इस संजीवनी योजना के तहत सभी वरिष्ठ नागरिकों को दिल्ली के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। बशर्ते कि वह दिल्ली का मूल निवासी हो। इस संजीवनी योजना के तहत इलाज में होने वाला सारा खर्च शामिल है।

बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर वो फिर से दिल्ली की सत्ता में लौटे, तो इस योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। खुद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ही इस योजना की शुरुआत की है। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मर्लिना भी उनके साथ थीं। इस रजिस्ट्रेशन के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लाभार्थियों को एक कार्ड उनके घर जाकर देंगे, जिसे सुरक्षित रखना है। क्योंकि इसी के आधार पर आगे की सभी सरकारी औपचारिकता आप की सरकार बनने के बाद पूरी की की जाएगी। इस योजना का मुख्य आकर्षण यह है कि इसमें इलाज के लिए कोई ऊपरी खर्च सीमा भी नहीं रखी गई है। यानी कि आपके इलाज का सारा खर्च सरकार वहन करेगी, चाहे वह जो भी हो।

इस प्रकार, संजीवनी योजना अन्य योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत योजना से काफी अलग है, क्योंकि इसमें इनकम को लेकर कोई नियम नहीं बनाया गया है। वहीं, यह योजना केंद्र सरकार की योजनाओं से भी स्वतंत्र है और इसका अपना एक अलग ढांचा है जो निकट भविष्य में दिल्ली सरकार खड़ा करेगी। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है। हालांकि, यह योजना पूरी तरह से केवल दिल्ली प्रदेश के निवासियों के लिए ही है, जिससे यहां रह रहे बाहर के लोगों को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। वहीं, इस योजना के लिए कोई समयसीमा भी नहीं रखी गई है। वहीं, दिल्ली प्रशासन ने साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार की संजीवनी योजना जैसी कोई योजना नहीं है। बता दें कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने इस बारे में एक नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अवैध तरीके से संजीवनी योजना के नाम पर पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में वरिष्ठ नागरिकों से आधार और बैंक खाता जानकारी मांगी जा रही है और नकली स्वास्थ्य योजना कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इसलिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जनता को सलाह दी है कि वे इस अनाधिकारिक योजना के तहत मुफ्त इलाज के वादों पर भरोसा न करें और अपनी संवेदनशील जानकारी साझा न करें।

खबर है कि दिल्ली प्रशासन के इस खुलासे से लोग असमंजस में हैं। वहीं, आप नेता दावे से कह रहे हैं कि जब वे चौथी बार सत्ता में आएंगे तो इस योजना को प्राथमिकता पूर्वक लागू करेंगे। तब इसी दिल्ली प्रशासन को निर्वाचित सरकार की हर बात माननी पड़ेगी। वैसे तो अभी भी दिल्ली में आप की ही सरकार है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आचार संहिता से बचने के डर से आप सरकार ने इसकी पूरी फ़ाइल नहीं चलाई। या फिर उसे इस बात का डर रहा होगा कि जब तक उपराज्यपाल की रजामंदी आएगी, तबतक चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी होगी। इसलिए आनन-फानन में आप रणनीतिकारों ने ताबड़तोड़ लोकलुभावन घोषणाएं शुरू कर दीं, जिनमें संजीवनी योजना भी एक मुख्य पहल है।

चुनाव प्रक्रिया को लेकर नहीं होनी चाहिए स्वार्थ की राजनीति

शशिधर खान

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने चुनाव प्रक्रिया पर उंगली उठानेवाले पराजित राजनीतिक दलों के झमेलों को एक सिरे से खारिज करते हुए मतदाताओं को ऐसे दुष्प्रचार से बचने को कहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा के दौरान सीईसी ने जोर देकर यह बात कही कि ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) किसी भी तरह से हैक नहीं हो सकती और मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों को नकारा। चुनाव आयोग की पूरी टीम के साथ सीईसी राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट समेत विभिन्न हाईकोर्ट आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि ईवीएम के 'फूलप्रूफ' और

छेड़छाड़ की संभावना से मुक्त होने के सत्यापन पर 42 बार अदालती मुहर लग चुकी है। गत हफ्ते दिल्ली विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के समय इस बार चुनाव आयोग का मुख्य फोकस मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर था। यह आरोप हाल में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस समेत इंडिया गठजोड़ ने उछाला है। महाराष्ट्र में हार की हताशा कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर मढ़ते हुए मतदाता सूची में गड़बड़ी को निशाना बनाया। राजीव कुमार ने उन आरोपों का सटीक और तथ्यपूर्ण खंडन करते हुए मतदाता सूची तैयार करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी 7 जनवरी को दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी।उन्होंने कहा कि संपूर्ण दस्तावेज देने, मौके पर पहुंचकर किए गए सत्यापन और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बगैर कोई नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता। चुनाव प्रक्रिया को राजनीतिक दलों ने सियासी हथकंडा बनाया हुआ है। हारने पर ईवीएम को जिम्मेदार ठहरानेवाले कोई भी राजनीतिक दल जीत का श्रेय ईवीएम को नहीं देते। मतलब ये कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुई, इसीलिए जीते। ईवीएम पर दोष मढ़नेवाली बयानबाजी करके हार को स्वीकार न करना इंडिया गठजोड़ में फूट का एक कारण बना है। जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एकमात्र नेता हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए चुनाव आयोग का शुक्रिया किया और कांग्रेस के ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों को गलत बताया। गत अक्तूबर में संपन्न जम्मू व कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी जीत मिली और उसके नेता उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिलीं कि अपनी शर्तों पर सरकार में शामिल हो सके। कांग्रेस नेताओं ने हार के लिए ईवीएम में छेड़छाड़ को दोषी ठहरा दिया। उनके जवाब में उमर अब्दुल्ला ने निष्पक्ष और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बिल्कुल पारदर्शी चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का शुक्रिया करते हुए कांग्रेस के आरोपों को हताशा का परिणाम बताया।

विघ्नहर्ता गणेश को ऐसे मनाएं

विघ्नहर्ता विनायक भगवान गणेश की पूजा यदि सच्चे मन से की जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। बुधवार भगवान गणेश का दिन होता है। बुधवार को गणेश की पूजा करें तो संतान, शिक्षा और भाग्य समृद्ध होता है। गणपति की उपासना से कुंडली के अशुभ योग भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कलयुग में उन्हें विघ्नविनाशक के रूप में पूजा जाता है। श्रीगणेश जी की बुधवार को पूजा करने का विधान हमारे धर्मग्रंथों में मौजूद है।

बुधवार को प्रात :काल में स्नानादि से निवृत होकर ताम्र पत्र के श्री गणेश यन्त्र को नमक, नींबू से अच्छे से साफ करें। यंत्र को शुद्ध जल से धोने के बाद पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर के आसान पर विराजमान हो कर सामने श्री गणेश यन्त्र की स्थापना करें। आसान पर बैठने के बाद दांयी हथेली में जल ले कर आसान व भूमि पर जल छिड़कते हुए नीचे लिखे मंत्र को पढ़ें....

ऊं अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा।
य: स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तर: शुचि:।।

अब गणेश यंत्र को शुद्ध जल चढ़ाते हुए मंत्र बोले

गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलऽस्मिन्सन्निधिं कुरु।।

यदि आप इस मंत्र की आराधना सच्चे मन से करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है।

फलदायी होती हैं हनुमान चालीसा की ये चौपाइयां

हनुमानजी की स्तुति हनुमान चालीसा से हम सभी परिचित हैं। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है कि बाल्यकाल में जब हनुमानजी ने सूर्य को मुंह में रख लिया तब सूर्य को मुक्त कराने के लिए देवराज इंद्र ने हनुमानजी पर शस्त्र से प्रहार किया। इसके बाद हनुमान जी मूर्छित हो गए। हनुमानजी के मूर्छित होने की बात जब वायु देव को पता चली तो काफी नाराज हुए। लेकिन जब सभी देवताओं को पता चला कि हनुमानजी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तब सभी देवताओं ने हनुमानजी को कई शक्तियां दी। देवताओं ने जिन मंत्रों और हनुमानजी की विशेषताओं को बताते हुए उन्हें शक्ति प्रदान की थी, उन्हीं मंत्रों के सार को गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में वर्णित किया है। हनुमान चालीसा में मंत्र नहीं हैं लेकिन हनुमानजी की पराक्रम की विशेषताएं बताई गई हैं। हनुमान चालीसा में ही ऐसी 5 चौपाईयां हैं, जिनका यदि नियमित सच्चे मन से वाचन किया जाए तो यह परम फलदायी सिद्ध होती हैं। हनुमान चालीसा का वाचन मंगलवार या शनिवार करना शुभ होता है। ध्यान रखें हनुमान चालीसा की इन चौपाइयों को पढ़ते समय उच्चारण की त्रुटि न करें।

भूत-पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे।।

उपाय- यदि व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय सताता है तो नित्य रोज प्रातः और सायंकाल में 108 बार इस चौपाई का जाप किया जाये तो सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है।

नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बल बीरा।।

उपाय- यदि व्यक्ति बीमारियों से घिरा रहता है तो निरंतर सुबह-शाम 108 बार जप करके तथा मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति के सामने पूरी हनुमान चालीसा के पाठ से रोगों की पीड़ा खत्म हो जाती है।

अष्ट-सिद्धि नवनिधि के दाता। अस बर दीन जानकी माता।।

उपाय- यदि जीवन में व्यक्ति को शक्तियों की प्राप्ति करनी है ताकि जीवन निर्वाह में मुश्किलों का कम सामना करना पड़े तो नित्य रोज, ब्रह्म मुहूर्त में आधा घंटा इन पंक्तियों के जप से लाभ प्राप्त हो सकता है।

विद्यावान गुनी अति चातुर। रामकाज करीबे को आतुर।।

उपाय- यदि किसी व्यक्ति को विद्या और धन चाहिए तो इन पंक्तियों के जप से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। प्रतिदिन 108 बार ध्यानपूर्वक जप करने से व्यक्ति के धन सम्बंधित दुःख दूर हो जाते हैं।

भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्रजी के काज संवारे।।

उपाय- यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है या व्यक्ति के कार्य नहीं बन पा रहे हैं तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए।

जैन मुनि को केश-लोचन करना अनिवार्य होता है

हाल ही में गुजरात 12वीं बोर्ड में 99.99 प्रतिशत हासिल करने वाले वर्शिल शाह जैन, जैन संत बन गए हैं। वर्शिल महज 17 साल के हैं और गुजरात के ही पालड़ी के रहने वाले हैं। दर्शिल अब जैन मुनि सुवीर्य रत्न विजयजी महाराज के नाम से जाने जाएंगे। पिछले वर्षों में गौर किया जाए तो युवाओं द्वारा संन्यास लेने की सिलसिला काफी बड़ा है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भले ही यह पूरा घटनाक्रम सकारात्मक हो, लेकिन जैन धर्म के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि जैन धर्म में संन्यास लेने वाले अनुयायी को मुनि की उपाधि दी जाती है। संन्यास लेने के बाद जैन मुनि को निर्ग्रन्थ भी कहा जाता है। मुनि शब्द पुरुषों के लिए तो आर्यिका शब्द स्त्री संन्यासियों को संबोधित किया जाता है। प्रत्येक जैन मुनि को केश-लोच करना अनिवार्य होता है।

तो क्या इतना प्राचीन है जैन धर्म

जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार यह धर्म अनादि और सनातन है। यदि आर्यों के भारत आने के बाद से भी देखा जाये तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि को लेकर जैन धर्म की परंपरा वेदों तक पहुंचती है। पुराणों में वर्णित है महाभारत के युद्ध के समय इस संप्रदाय के प्रमुख नेमिनाथ थे, जो जैन धर्म में मान्य तीर्थंकर हैं। आठवीं सदी में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जिनका जन्म काशी में हुआ था। काशी के पास ही 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर सारनाथ का नाम प्रचलित है। जैन धर्म में श्रमण संप्रदाय का पहला संगठन पार्श्वनाथ ने किया था। ये श्रमण वैदिक परंपरा के विरुद्ध थे। महावीर तथा बुद्ध के काल में ये श्रमण कुछ बौद्ध तथा कुछ जैन हो गए थे। इन दोनों ने अलग-अलग अपनी शाखाएं बना लीं। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म लगभग ई.पू. 599 में हुआ और जिन्होंने 72 वर्ष की आयु में देहत्यागी। महावीर स्वामी ने शरीर त्यागने से पहले जैन धर्म की नींव काफी मजबूत कर दी थी। अहिंसा को उन्होंने जैन धर्म में अच्छी तरह स्थापित कर दिया था। सांसारिकता पर विजयी होने के कारण वे जिन (जयी) कहलाए। उन्हीं के समय से इस संप्रदाय का नाम जैन हो गया।

क्या आप भी भगवान को फूल चढ़ाते हैं

राजा राम मोहन राय के बगीचे में बड़े ही सुंदर फूलों के पेड़ लगे थे। एक व्यक्ति था जो हर रोज वहां आता और उनसे पूछे बिना ही पूजा के लिए फूल तोड़ कर ले जाता। यह सिलसिला लगातार कई दिनों तक चलता रहा। रोज की तरह ही एक दिन उस व्यक्ति ने फूल तोड़ने के लिए अपनी चादर उतारी और पेड़ पर लटका कर फूल तोड़ने लगा। उसी समय राजा राम मोहन राय के आदेशानुसार एक सेवक ने उस व्यक्ति की वह चादर उठा ली और राजा राम मोहन राय को दे दी।

फूल तोड़ने के बाद जब वह व्यक्ति अपनी चादर लेने के लिए उस पेड़ के पास गया, जहां उसने उसे लटकाई थी, तो वहां चादर न देख वह हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर उसकी चादर गई कहां? वह गुस्से से आग-बबूला हो गया। कुछ देर बाद राजा राम मोहन राय आए और उन्होंने उस व्यक्ति को उसकी चादर लौटाते हुए कहा, 'अब तो खुश हैं आप, आपको आपकी चादर वापस मिल गई।

उस व्यक्ति ने गुस्से में ही जवाब दिया, खुश? इसमें खुश होने वाली कौन-सी बात है, मुझे अपनी ही वस्तु मिली है।''

राजा राम मोहन राय ने उस व्यक्ति से पूछा, आप रोज फूल तोड़कर कहां ले जाते हैं?

उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं ये फूल तोड़कर मंदिर में ले जाता हूं। भगवान को खुश करने के लिए उनको ये फूल अर्पित करता हूं।

राजा राम मोहन राय ने उस व्यक्ति का यह जवाब सुनकर कहा, पहली बात तो यह कि आप बिना पूछे ही फूल तोड़कर ले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को अर्पित करते हैं, तो इससे भगवान खुश होते हैं क्या?

उस व्यक्ति ने कहा, क्यों नहीं, भगवान को फूल ही तो पसंद हैं, भगवान को फूलों से खुशी मिलती है।

राजा राम मोहन राय ने उस व्यक्ति से कहा, तो आपको चादर मिलने पर खुशी क्यों नहीं हुई?

राजा राम मोहन राय की यह बात सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और राजा राम मोहन राय बिना कुछ और कहे लौट गए।

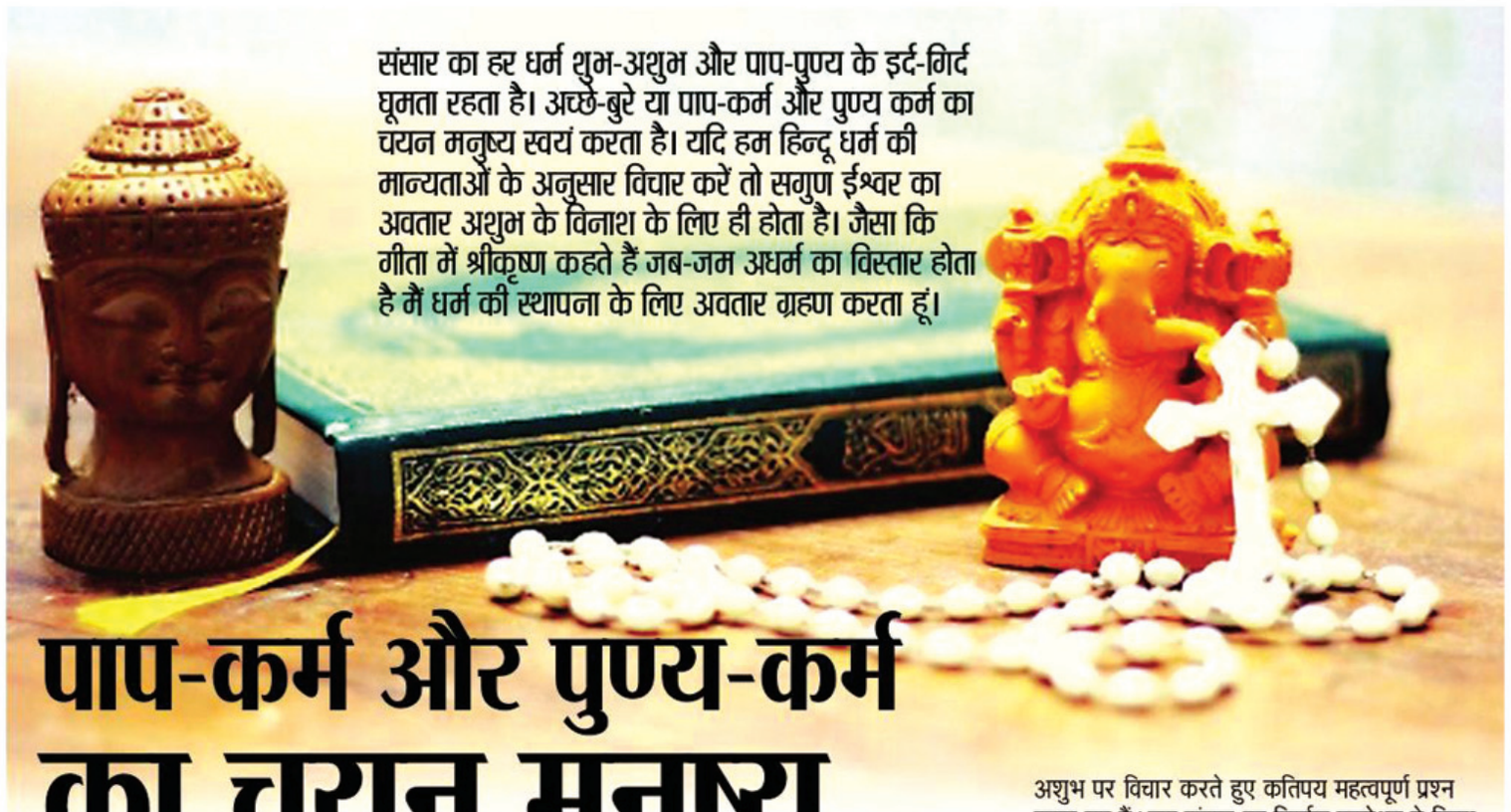

संसार का हर धर्म शुभ-अशुभ और पाप-पुण्य के इर्द-गिर्द घूमता रहता है। अच्छे-बुरे या पाप-कर्म और पुण्य कर्म का चयन मनुष्य स्वयं करता है। यदि हम हिन्दू धर्म की मान्यताओं के अनुसार विचार करें तो सगुण ईश्वर का अवतार अशुभ के विनाश के लिए ही होता है। जैसा कि गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं जब-जम अधर्म का विस्तार होता है मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार ग्रहण करता हूं।

पाप-कर्म और पुण्य-कर्म का चयन मनुष्य स्वयं करता है

शुभ और अशुभ व पुण्य और पाप की समस्या कर्म-फल-सिध्दांत पर आधारित हैं। जीव यदि अशुभ कर्मों की ओर प्रेरित होता है तो इसके पीछे उसकी अल्पज्ञता, अज्ञान होता है। संसार का हर धर्म शुभ-अशुभ और पाप-पुण्य के इर्द-गिर्द घूमता रहता है। ईसाई धर्म में ईश-चिंतन के संदर्भ में उक्त विचारधारा प्राप्त होती है। ईश्वर परम शुभ है। अत: उस पर पाप या अशुभ का आरोपण नहीं किया जा सकता। बाइबिल में काम-वासना को पाप या अशुभ की संज्ञा दी गई है और उसका शैतान कहा गया है। ईसाई नीतिशास्त्र में पाप या अशुभ पर विचार करते हुए कतिपय महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। इस संसार का निर्माण परमेश्वर ने किया, किन्तु संसार में सर्वत्र पाप ही पाप है। यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और ईश्वर शुभ और सर्वशक्तिमान है तो सृष्टि में शुभ ही शुभ होना चाहिए। ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता प्रदान की है। अत- अच्छे-बुरे या पाप-कर्म और पुण्य कर्म का चयन मनुष्य स्वयं करता है। यदि हम हिन्दू धर्म की मान्यताओं के अनुसार विचार करें तो सगुण ईश्वर का अवतार अशुभ के विनाश के लिए ही होता है। जैसा कि गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं जब-जम अधर्म का विस्तार होता है मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार ग्रहण करता हूं। बाइबिल में ईसा मसीह को पुत्रेश्वर कहा गया है। परमेश्वर के पुत्र के रूप में ईसा मसीह संसार के पापों को दूर करने के लिये-ही धरती पर आए थे।

मालवा की वैष्णो देवी नीमच की भादवा माता

गुप्त नवरात्र शुरू हो गए हैं। इस मौके पर हम आपको एक ऐसे शक्तिपीठ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कृपा से शहर में कोई भूखा नहीं सोता। किसी के पास पैसे की तंगी नहीं रहती है। लोक कथाओं के अनुसार, हरसिद्धि मंदिर में उज्जैन के राजा रहे विक्रमादित्य की आराध्य देवी का वास है। शिवपुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में माता के सती हो जाने के बाद भगवान भोलेनाथ सती को उठाकर ब्रह्मांड में ले गए थे। इस दौरान माता सती के अंग जिन स्थानों पर गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। कहा जाता है इस स्थान पर माता के दाहिने हाथ की कोहनी गिरी थी और इसी कारण से यह स्थान भी एक शक्तिपीठ बन गया है। स्कंद पुराण के अनुसार, देवी को चंड एवं मुंड नामक राक्षस के वध के लिए भगवान शिव से सिद्धि मिली थी, इसीलिए वह हरसिद्धि कहलाईं। गर्भगृह में एक शिला पर श्रीयंत्र उत्कीर्ण है, जो शक्ति का प्रतीक है। यहां माता लक्ष्मी, महासरस्वती के साथ ही अन्नपूर्णा माता विराजमान हैं। यह स्थान उज्जैन के प्राचीन देवी स्थानों में अपना विशेष महत्व रखता है। वर्तमान में मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय मराठों को जाता है। मंदिर के सामने मराठा वास्तुकला के अनुसार दीप स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जिनमें 1001 दिये बने हुए हैं। दक्षिण में बनी एक बावड़ी पर 1447 संवत का एक शिलालेख भी उत्कीर्ण है। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित शेषनारायण गोस्वामी ने बताया कि गर्भगृह में सबसे ऊपर विराजमान हैं मां अन्नपूर्णा, जिनकी वजह से उज्जैनी में हमेशा भंडारे चलते रहते हैं। कहा जाता है कि उनकी कृपा से उज्जैन में कोई भूखा नहीं सोता है। बीच में मां लक्ष्मी के स्वरुप में है, जिनकी वजह से किसी को भी लक्ष्मी की कमी नहीं आती। सबसे नीचे विराजित हैं महाकाली।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के खिलाफ अपने बयानों के लिए दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रोक दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा द्वारा राहुल के खिलाफ दायर मानहानि मामले को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसे कई फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है और प्रॉक्सी पार्टी द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है। वहीं, मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा को नोटिस भेजा है।

दिल्ली चुनाव में बेहतर विकल्प के रूप में उभरी कांग्रेसः सचिन

नईदिल्ली। दिल्ली चुनाव से पहले, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राजधानी के लोग आप के नेतृत्व वाली शहर सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पीड़ित हैं, और उनकी पार्टी बेहतर विकल्प के रूप में उभरी है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस को वोट देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच वर्चस्व की लड़ाई है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेहतर विकल्प बनकर उभरी है और लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसे जनादेश देंगे। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के लोगों को कुछ गारंटी दी है। उन्हें शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के तहत हुआ विकास भी याद है। हम मजबूती से लड़ेंगे और कांग्रेस दिल्ली चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी।

सैफ पर हमला करने वाला बांग्लादेशी, केजरीवाल चुप

नईदिल्ली। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हमले को लेकर केंद्र सरकार से इस्तीफे की मांग करने वाले आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए भाजपा ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री यह जानने के बाद से चुप हैं कि हमलावर बांग्लादेशी घुसपैठिया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि फिल्म स्टार सैफ अली खान के ऊपर अटैक होने के दिन चिल्लाने वाले अरविंद केजरीवाल ने यह पता लगते ही की हमलावार बांग्लादेशी है चुप्पी साध ली है। सचदेवा ने कहा कि भाजपा पहले दिन से कह रही है कि दिल्ली ही नहीं देश के लिए रोहिग्या और बांग्लादेशी सुरक्षा खतरा बन गये हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आश्रय देते हैं, उन्हें पालने का काम करते हैं। मुंबई पुलिस ने पहले दिन में कहा था कि बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, जो अवैध रूप से भारत में आया था और अपना नाम बदलकर बिजॉय दास रख लिया था।

उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारियां तेज

देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य सचिवालय में आयोजित एक बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली को मंजूरी दे दी। अधिकारियों के अनुसार, यह विकास विधायी विभाग द्वारा मैनुअल की सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद हुआ। मंजूरी के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के चुनावों से पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। धामी ने कहा कि हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम यूसीसी बिल लाएंगे। हम इसे ले आये। मसौदा समिति ने इसका मसौदा तैयार किया, यह पारित हुआ, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह एक अधिनियम बन गया। ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हर चीज का विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे।

नीतीश सरकार ने केंद्र को भेजा 32 पन्नों का ज्ञापन

पटना। पिछले साल के बजट ने बिहार के साथ-साथ आंध्र प्रदेश में दो महत्वपूर्ण सहयोगियों की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अपना बटुआ खोल दिया था, जिन्होंने अपने दम पर बहुमत से पीछे रहने के बाद केंद्र में भाजपा को सरकार बनाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वर्ष के लिए, बिहार ने पहले ही सीतारमण को 32 पन्नों का एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें केंद्र से बिहार के विकास के लिए उदार धन आवंटित करने का आग्रह किया गया है। प्रमुख मांगों में, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उत्तर बिहार में वार्षिक बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए ऊंचे बांध बनाने के लिए नेपाल सरकार के साथ सहयोग करने का आह्वान किया है। चौधरी ने बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के तहत गंडक, कोसी और कमला जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय नदियों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया।

संविधान पर हो रहा हमला, कांग्रेस बोली-

राष्ट्रविरोधी बयान के लिए मोहन भागवत को मांगनी होगी माफी

नईदिल्ली। कर्नाटक के बेलगावी में अपनी जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली से पहले, कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि संविधान पर हमला हो रहा है और अपनी मांग दोहराई कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को स्वतंत्रता आंदोलन पर दिए गए राष्ट्रविरोधी बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। विपक्षी दल ने यह भी दावा किया कि महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है और बीआर अंबेडकर पर हमला किया जा रहा है।

कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कल कांग्रेस की जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली बेलगावी में होगी। यह 27 दिसंबर, 2024 को होना था लेकिन डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बेलगावी में ही महात्मा गांधी ने 26 दिसंबर, 1924 को कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला था। आज महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर पर हमला किया जा रहा है। भारत के संविधान और उसके मूल्यों पर आक्रमण हो रहा है।

जयराम रमेश ने कहा कि बेलगावी रैली महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर की विरासत को संरक्षित करने और उन्हें आगे ले जाने के कांग्रेस के दृढ़ संकल्प की पुष्टि है। इसके बाद 27 जनवरी को डॉ. अंबेडकर की जन्मभूमि महू में भी इसी तरह की रैली होगी। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को 14 जनवरी 2025 को स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर दिए अपने घृणित और राष्ट्र-विरोधी बयान के लिए माफी मांगनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री को 17 दिसंबर, 2024 को संसद में डॉ. अंबेडकर पर की गई अपनी अपमानजनक टिप्पणी के लिए इस्तीफा देना होगा और माफी मांगनी होगी।

कांग्रेस ने बार-बार यह भी आरोप लगाया है कि शीतकालीन सत्र के दौरान संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी से पता चलता है कि भाजपा और आरएसएस नेताओं

को अंबेडकर के प्रति बहुत नफरत है और उनसे माफी की मांग की गई है। पार्टी के एक परिपत्र में कहा गया था कि महू में रैली संविधान की 75वीं वर्षगांठ और भारत के गणतंत्र की स्थापना के साथ-साथ सत्तारूढ़ शासन द्वारा बाबासाहेब अंबेडकर की विरासत पर कथित हमले का जश्न मनाएगी।

भाजपा को सबक सिखाएगी मिल्कीपुर की जनता : कांग्रेस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र में आगामी उपचुनाव के लिए अपने इंडिया ब्लॉक सहयोगी समाजवादी पार्टी को पूरी ताकत से समर्थन दिया। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रही है। चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना भाजपा का काम है लेकिन मिल्कीपुर की जनता इस बार उन्हें सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस ने मिल्कीपुर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है और इसके बजाय उसने सपा उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है। पिछले साल हुए आम चुनाव में फैजाबाद से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के अवधेश प्रसाद द्वारा सीट खाली करने के बाद मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जरूरी हो गया था। मिल्कीपुर उपचुनाव 5 फरवरी को होना है और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी।

मंत्रियों की नियुक्ति के महायुति के तरीके से गठबंधन में आंतरिक कलह का पता चलता है: राउत

मुंबई । शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ 'महायुति' सरकार के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति का तरीका गठबंधन में आंतरिक कलह का संकेत है। राज्य सरकार ने शनिवार को राज्य के 36 जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की घोषणा की, लेकिन एक दिन बाद नासिक और रायगढ़ के लिए नियुक्तियों पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की अदिति तटकरे को रायगढ़ का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता गिरीश महाजन को नासिक की जिम्मेदारी दी गई थी।

राउत ने पत्रकारों से कहा, ''सरकार अपने अंदरूनी विवादों से निपटने में विफल रही है। (उपमुख्यमंत्री) एकनाथ शिंदे का प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति पर गुस्सा स्पष्ट है।'' शिवसेना (उबाठा) नेता रायगढ़ और नासिक में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियों को लेकर एकनाथ शिंदे के असंतोष की खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राज्य के उद्योग मंत्री एवं शिवसेना नेता उदय सामंत को शिंदे की जगह संभावित नेता के रूप में तैयार किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, शिंदे अचानक अपने पैतृक गांव दरेगांव के लिए रवाना हो गए। आधिकारिक तौर पर उन्होंने अपने चार-दिवसीय दौरे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है

हालांकि, राजनीतिक अंदरूनी सूत्रों का अनुमान है कि उनका जाना विभागों को लेकर उनके असंतोष से जुड़ा है। राउत ने दावा किया कि बढ़ती कलह सत्ता में बदलाव ला सकती है। उन्होंने कहा, ''ऐसा लगता है कि उदय सामंत को शिंदे की जगह संभावित नेता के रूप में तैयार किया जा रहा है। अगर शिंदे अपने मंत्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो वे नेतृत्व कैसे कर सकते हैं?'' असंतोष की खबरों के बीच, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और गिरीश महाजन शिंदे से मिलने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए दरेगांव के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस समय विश्व आर्थिक मंच में हिस्सा लेने के लिए दावोस में हैं।

सांप्रदायिकता फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे: अजित पवार

जालना में राकांपा के जिला कार्यालय का किया उद्घाटन

जालना (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) धर्मनिरपेक्ष राजनीति में भरोसा करती है और राज्य में सांप्रदायिकता फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र हमेशा प्रगतिशील विचार और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक रहा है। राकांपा एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए खड़ी है।

जालना में राकांपा के जिला कार्यालय का उद्घाटन करते वक्त अजित पवार ने कहा, हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो विभिन्न समुदायों में नफरत फैलाए और बांटने की राजनीति करे। उन्होंने कहा कि राकांपा में खराब छवि वाले या दागी लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं पार्टी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे हमारी पार्टी में दागी लोगों को शामिल न करें।

इसके अलावा, अजित पवार ने %माझी लड़की बहिन योजना% के लिए जो महिलाएं पात्र नहीं हैं, उनसे अपील की कि वे स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ दें। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के लिए है। पवार ने कहा, जो लोग आयकर का भुगतान करते हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्हें स्वेच्छा से इस लाभ को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि पात्र लाभार्थियों को अगले महीने से उनके मासिक भत्ते मिलेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर उन्होंने विपक्षी पर दोहरे रुख का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब विपक्ष दल कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम की तारीफ करते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो उन्हीं मशीनों पर आरोप लगाते हैं। पवार ने राकांपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तैयार रहें।

वडेट्टीवार का महाराष्ट्र सरकार पर वार

मुंबई। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हटाया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि शिवसेना एक नया उदय देख सकती है। कांग्रेस नेता ने यह उदय सावंत के संदर्भ में कहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति पर एकनाथ शिंदे की असंतुष्टि की अटकलों पर प्रतिक्रिया दी। सूत्रों ने बताया कि शिंदे निजी कारणों से अपने पैतृक गांव सतारा के लिए रवाना हो चुके हैं।

नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में एकनाथ शिंदे की हालत बहुत खराब है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें किनारा किया जा सकता है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या शिंदे की राजनीतिक उपयोगिता खत्म हो चुकी है? उद्धव ठाकरे को बाहर कर एकनाथ शिंदे को लाया गया था।

भाजपा पर हमला करते हुए वडेट्टीवार ने दावा किया कि महाराष्ट्र में शिवसेना के उदय की संभावना के साथ राजनीतिक स्थिति बन सकती है। उन्होंने कहा, एक उदय (राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत) दोनों नावों में यात्रा कर रहे हैं और (दोनों पक्षों के साथ) बहुत अच्छे संबंध बनाए हुए हैं।

बता दें कि फडणवीस सरकार ने शनिवार को 36 जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी की थी। राकांपा की अदिति तटकरे रायगढ़ की प्रभारी मंत्री नियुक्त हुईं। इससे शिवसेना नेता भरत गोगावाले नाराज हो गए। दरअसल उन्होंने बताया था कि वे रायगढ़ के प्रभारी मंत्री बनने के इच्छुक हैं। भाजपा के गिरीश महाजन को नासिक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और गिरीश महाजन एकनाथ शिंदे से मिलने दारेगांव के लिए रवाना हुए।

खेल
प्रमुख समाचार

आखिरकार भारतीय टीम से जुड़े मोहम्मद शमी

कोलकाता। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ सफेद गेंद की सीरीज के शुरुआती मैच से पहले रविवार को यहां जब अपने तीन घंटे के अभ्यास सत्र के लिए एकत्र हुई तो सभी की नजरें तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर थी। चोट के कारण 14 महीने के लंबे अंतराल पर राष्ट्रीय टीम में वापसी करते हुए शमी ने एक घंटे से अधिक समय तक पूरी लय में गेंदबाजी की।

अपने बाएं घुटने पर भारी पट्टी बांधकर शमी ने गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल की निगरानी में शुरुआत में छोटे रनअप के साथ धीमी गेंदबाजी की और फिर पूरे रनअप के साथ गेंदबाजी की गति को बढ़ाया। उन्होंने लगभग एक घंटे तक गेंदबाजी करने के बाद क्षेत्ररक्षण अभ्यास में भी हिस्सा लिया। शमी की फिटनेस को लेकर संदेह था। उन्होंने अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे युवा बल्लेबाजों को अपनी गति और सटीक लाइन लेंथ से परेशान कर हर तरह की चिंताओं को दूर किया।

इस दौरान विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने उनके खिलाफ कुछ आक्रामक शॉट लगाए। गेंदबाजी अभ्यास खत्म करने के बाद उन्होंने गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल से बातचीत की। शमी को टी20 टीम में शामिल किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि टीम 19 फरवरी से दुबई और पाकिस्तान में शुरू होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपने तेज आक्रमण को मजबूत करना चाहती है।

जसप्रीत बुमराह की चोट को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है ऐसे में शमी की फिटनेस भारत की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शमी ने घरेलू क्रिकेट से वापसी करने के बाद राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के बाद विजय हजारे वनडे ट्रॉफी में भी भाग लिया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 454 अंक चढ़ा निफ्टी 23,300 के पार

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटव रुझानों और बैंकिंग और मेटल शेयरों में तेजी के दम पर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में फिर से तेजी लौट आई। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 450 अंक और निफ्टी 141 अंक की बढ़त 23,300 के पार बंद हुआ। 30 शेयरों वाला, बीएसई सेंसेक्स 454.11 अंक यानी 0.59% की बढ़त लेकर 77,073.44 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 77,318.94 और 76,584.84 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ 50 शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी-50 141.55 अंक यानी 0.61% की बढ़त लेकर 23,344.75 पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 23,391.10 और 23,170.65 के रेंज में कारोबार हुआ। सेंसेंक्स के 30 शेयरों में 17 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। कोटक बैंक, बजाज फाइनैंस, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी और एसबीआई सेंसेक्स के टॉप-5 गेनर्स रहे।

तीसरी तिमाही के बाद आईटी शेयरों में बड़ा मौका!

नईदिल्ली। सोमवार का दिन विप्रो के लिए किसी जश्न से कम नहीं था। कंपनी के शेयर 8% की छलांग लगाते हुए रू. 302 पर पहुंच गए। ये तेजी शुक्रवार को आए तीसरी तिमाही नतीजों के बाद आई। वहीं दूसरी तरफ, बाकी आईटी कंपनियों के शेयर सुस्त नजर आए। निफ्टी 50 इंडेक्स तो थोड़ा ऊपर चढ़कर 23,270 पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आईटी इंडेक्स का मूड खराब था, जो 0.1% की गिरावट के साथ 42,000 के स्तर तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि आईटी सेक्टर के बड़े प्लेयर्स की कमाई रिपोर्ट ने निवेशकों को ज्यादा खुश नहीं किया। अब जरा तीसरी तिमाही नतीजों पर नजर डालें तो, विप्रो ने 24.5% की जबरदस्त बढ़त के साथ रू. 3,350 करोड़ का मुनाफा कमाया। टीसीएस और इंफोसिस ने 12% की ग्रोथ दिखाई, जबकि एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने थोड़ा निराश करते हुए सिर्फ 6% की बढ़त दर्ज की।

पेटीएम का घाटा घटकर 208 करोड़ रू., रेवेन्यू में आई गिरावट

नईदिल्ली। फिनटेक कंपनी पेटीएम (वन97 कम्युनिकेशंस) ने सोमवार को अपने वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड घाटा घटकर 208.3 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 219.8 करोड़ रुपये था। हालांकि, पेटीएम का रेवेन्यू 36 फीसदी की गिरावट के साथ 1,828 करोड़ रुपये पर दर्ज किया गया। यह Q3FY24 में यह 2,851 करोड़ रुपये था। कंपनी की अन्य स्रोतों से इनकम 149 करोड़ रुपये से बढ़कर 189 करोड़ रुपये हो गई। पेटीएम के तीसरी तिमाही नतीजों के बाद कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली। पेटीएम ने सालाना और तिमाही आधार पर अपने खर्चों में कटौती की है। वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में फिनटेक फर्म ने 3216.3 करोड़ रुपये खर्च किए, जो वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 31 फीसदी घटकर 2219.8 करोड़ रुपये रह गया। तिमाही आधार पर खर्च 2244.8 करोड़ रुपये से 1.1 फीसदी कम रहा।

लग्जरी सेगमेंट में 80 प्रतिशत बढ़ी सेल्स

नईदिल्ली। भारत में पहली बार 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले अपार्टमेंट्स ने सलाना आवासीय बिक्री के 50% से अधिक हिस्से पर कब्जा जमाया। यह भारत में घर खरीदने वाले लोगों के प्राथमिकताओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दिखाता है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म जेएलएल द्वारा जारी 2024 की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। आरईआईएस इंडिया के प्रमुख और मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. समंतक दास के अनुसार, अपार्टमेंट्स की खरीददारी के प्रीमियम सेगमेंट (3-5 करोड़ रुपए) में 86% और लग्जरी सेगमेंट (5 करोड़ रुपए और ऊपर) में 80% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो 2023 की तुलना में बहुत अधिक है। इस बढ़ोतरी के पीछे हाई-नेट-वर्थ लोगों की आय में बढ़ोतरी, टेक-एनेबल्ड घरों की मांग और लोगों को बीच सुरक्षित घरों की बढ़ती प्राथमिकताएं बड़े कारण हैं।

यह कैसी केवाईसी... कई बैंकों की प्रक्रिया प्रताड़ना से कम नहीं

संजय अभिज्ञान

आगामी एक फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से आम नागरिकों की सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? जवाब के लिए आज कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण हो, तो मुमकिन है कि पब्लिक के दिल की आवाज कुछ इस तरह सुनाई दे कि वित्त मंत्री जी, बाकी तो हम झेल लेंगे, मगर सबसे पहले बैंकों में बारंबार केवाईसी वेरिफिकेशन के जंजाल से छुटकारा दिलाइए।

हर चार-पांच माह की अवधि के बाद आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ, फोटो और मोबाइल नंबर के दस्तावेज सत्यापित कराने की कवायद की पीर वही जानते हैं, जो इसे भुगत चुके हैं। 'अपने ग्राहक को जानो'-के ऊंचे स्लोगन के साथ केवाईसी की चक्की सबको पीस रही है। इधर कुछ बैंकों ने जिस तरह केवाईसी अपडेशन के लिए खाते में लेनदेन रोकने जैसी हद पार करने वाली हरकत का सहारा लेना शुरू किया है, उससे यह जनउत्पीड़न का आकार ले रहा है। शहरों-कस्बों के निवेशक, बचतकर्ता, म्यूचुअल फंड ग्राहक और किस्म-किस्म के लोनधारकों के अलावा देहात के वे गरीब लाभार्थी ज्यादा दुख झेल रहे हैं, जो अपनी सब्सिडी की किस्त, राशन भुगतान, सम्मान राशि या पेंशन जनधन खाते में गिरने का इंतजार करते रह जाते हैं। यह वही तबका है, जो पहले से न्यूनतम बैलेंस के नियम के कारण निष्क्रिय खातों का कहर झेल रहा था।

यूपी की एक ताजा घटना देखें। वाराणसी के पास सोनभद्र में पिछले साल 28 दिसंबर को बैंक की लाइन में खड़े 65 वर्षीय रम्मन अचानक गिर गए। अस्पताल पहुंचने पर वह मृत पाए गए। सभी स्थानीय अखबारों में यह खबर छपी और उसकी सुर्खियों में केवाईसी को जिम्मेवार बताया गया। परिवार का

आरोप था कि वह तीन दिन से पेंशन खाते की केवाईसी के लिए बैंक का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कभी सर्वर डाउन होने के कारण और कभी किसी और वजह से काम पूरा नहीं हो पा रहा था। इस घटना से देश के वित्तजगत को चौंक जाना चाहिए था। खाते में लेनदेन रुक जाए और यूपीआई वगैरह के भुगतान ठप हो जाएं। देश में एक लाख साठ हजारसे ज्यादा बैंक शाखाएं हैं। लेकिन विसंगति है कि इनमें से बस 30 फीसदी ग्रामीण भारत में हैं, जहां देश की 60 फीसदी आबादी बसती है। शाखाओं के इस कम घनत्व के कारण ही वहां घर से बैंक शाखा तक का फासला कई किलोमीटर लंबा होता है। इस नई लीला के पीछे कौन है? जाहिर है जिस केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में देश के 53 करोड़ लोगों को जनधन खाता देने की ऐतिहासिक वित्तीय समावेशी योजना बनाई, वह क्यों चाहेगी कि खाता धारकों के साथ ऐसा सलूक हो। न ही रिजर्व बैंक चाहेगा, क्योंकि उसने तो वर्ष 2016 में जारी अपने मास्टर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में साफ लिखा है कि केवाईसी में पहचान पत्र, पता, मोबाइल और ईमेल ही पर्याप्त हैं। यही नहीं, 6 नवंबर, 2024 को जारी नोटिफिकेशन में रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर कस्टमर के केवाईसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ईमेल से भेजा गया उसका सेल्फ डिक्लेरेशन भी सत्यापन के लिए पर्याप्त होगा। नियम यह भी है कि यदि कस्टमर सामान्य रिस्क श्रेणी वाला है, तो दस साल में एक बार सत्यापन भी मान्य होगा। मगर कितने बैंक हैं, जहां इन नियम-कायदों की अनदेखी नहीं हो रही? वित्तीय लेनदेन की निगरानी वाले बिचौलिए विभाग और कुछ रिटेल बैंक विलेन बनकर उभर रहे हैं। उधर अनेक केस स्टडी देख चुके विशेषज्ञ बताते हैं कि केवाईसी के बहाने बीमा या म्यूचुअल फंड जैसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की बिक्री का माहौल बनाया जाता है।

कई जगह गांव-देहात में जनधन खाते खोलने का टारगेट पूरा करने की होड़ में कतिपय कर्मियों ने खासी हड़बड़ी में केवाईसी की जानकारी दर्ज की थी। डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्कों के स्तर पर हुई गलतियां तो अपनी जगह हैं ही, कोढ़ में खाज की तरह आधार कार्ड में दर्ज हुई पुरानी गलतियां भी उनमें जुड़ जाती हैं। अब जब यह मोबाइल और पैन से लिंक हो गया है- उसकी एक-एक बारीकी नाजुक हो चली है। बेशक, ऑनलाइन धोखाधड़ी के चलते केवाईसी की पड़ताल आवश्यक है।

85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए डॉ. रमन सिंह

संविधान की सफलता के पीछे भारतीय जनता की शक्ति

पटना। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी ने आज बिहार की राजधानी पटना में आयोजित 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष जी ने संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने में संसद एवं राज्य विधान मंडलों के योगदान के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए डॉ. रमन सिंह जी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। सामान्य तौर पर यही कहा जाता है कि यह व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। लेकिन भारत में संविधान के आधार पर शासन भी अंग्रेजों की देन नहीं है, भारत में वैदिक काल से सभा, समिति एवं गण जैसी परामर्शदात्री संस्थाओं का अस्तित्व रहा है।

भारत में महाजनपद काल में वज्जिसंघ भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते थे। सभा और नगरम् जैसी पंचायतें और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन संस्थाएं भी संचालित रहीं। जनता ही इन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती थी।

उन्होंने आगे कहा कि जिस पटना की भूमि पर यह सम्मेलन हो रहा वह पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक भूमि है जहाँ महान मौर्य वंश की शुरुआत हुई। उस समय का शासन प्रबंध कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित था। वह उस काल का संविधान ही था, जिस पर आधारित शासन व्यवस्था 500 वर्षों तक चलता रहा।

आगे डॉ रमन सिंह ने कहा कि भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जनता के द्वारा संबोधित एवं राष्ट्र को समर्पित उद्देशिका की शुरुआत होती है 'हम भारत के लोग' और समाप्त होता है 'इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा समर्पित करते हैं।' इसका अर्थ है कि भारत का संविधान देश की जनता की भावना का प्रतिबिंब है। यह भावना स्वतंत्रता के बाद बनाए गए संविधान की ही नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की भारत की राजनीतिक यात्रा का प्रतीक है।

उन्होंने कहा: संविधान की सफलता के पीछे भारतीय जनता की शक्ति है। संसद और विधान मंडलों ने संविधान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका प्रमुख दायित्व देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। उदाहरण स्वरूप, डॉ रमन सिंह ने बताया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत की अखंडता को बनाये रखने के लिए अलग विधान से संचालित कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर संसद ने भारत की एकता और अखंडता को सशक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया है। वहीं देश में आरटीआई (शिक्षा के अधिकार कानून) ने पूरे देश में एकता और शिक्षा के प्रति सभी को अधिकार दिया है। इसी भावना को छत्तीसगढ़ में उतरते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित भोजन का अधिकार कानून ने हर ग़रीब की थाली तक भोजन सुनिश्चित किया और कौशल उन्नयन का अधिकार कानून लागू कर प्रदेश के युवाओं को अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान किया है।

डॉ. रमन सिंह जी ने अगले 25 वर्षों में संसद और विधान मंडलों के योगदान पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के संविधान के 75वें वर्ष में यह संतोषजनक है कि हजारों वर्षों की गुलामी से उबरकर भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बना है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु संसद और विधान मंडलों को प्रमुख योगदान देना होगा।साथ ही संसद और विधान मंडलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डिजिटल तकनीकों से लैस करना, जनप्रतिनिधियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना और जनता तक उनकी पहुँच बढ़ानी होगी। जनता का विश्वास अर्जित कर संसद और विधान मंडलों को अधिक उत्तरदायी बनाना ही देश के समग्र विकास की कुंजी है।

डॉ. रमन सिंह के इस वक्तव्य ने संविधान, संसद और विधान मंडलों के महत्व को उजागर किया और देश के विकास में इनके भविष्य के योगदान की दिशा को रेखांकित किया।

मेरी बात

✍ गिरीश पंकज

कुम्भ एक सांस्कृतिक उत्सव

144 साल के बाद आया है यह महाकुंभ. प्रश्न यह है कि कुंभ तो कुंभ है, फिर यह यह महाकुंभ क्यों है. इसका उत्तर यही है कि इसके पहले ग्यारह कुंभ आ चुके हैं. ग्यारहवें कुंभ के बाद जो कुंभ आता है, उसे महाकुंभ कहा जाता है और यह आदिकाल से चला रहा है. इस वर्ष के कुंभ को इसीलिए महाकुंभ कहा जा रहा है. इस महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए दुनिया भर के सनातन प्रेमी पधार रहे हैं. मैं यह देखकर अभिभूत हूं कि प्रयागराज में में विदेश के भी अनेक श्रद्धालु मगन होकर डाल रहे हैं. मुख्यमंत्री के सामने उपस्थित होकर शिव तांडव स्त्रोत और रामचरितमानस की चौपाइयां सुन रहे हैं. यह है सनातन का असर. कुछ सनातन विरोधी हिंदू तथाकथित प्रगतिशीलता के रौ में बह कर ठंडी को कोस रहे हैं. प्रयागराज की भीषण ठंड में कुछ लोग मर गए. एक वामपंथी चिंतक ने लिखा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है. वह परोक्ष रूप से मोदी सरकार को लांक्षित करने की कोशिश में थे. उनकी बातों से यही ध्वनि हो रहा था. जबकि ठंड तो हर साल पड़ती है. हर साल लोग प्रयागराज के संगम में जाकर स्नान करते हैं. प्रतिवर्ष कल्पवास होता है. माघ मेला लगता है. इसी तरह की भीषण ठंड पड़ती है. लेकिन लोग पूरी श्रद्धा के साथ जाते हैं. वहां स्नान करते हैं. मेरे पिताजी भी लंबे समय तक वहां जाते रहे. कुछ कमजोर शरीर वाले दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं. लेकिन जिनकी आस्था, श्रद्धा मजबूत होती है, इच्छा शक्ति भी, वे डुबकी लगा कर बाहर निकल जाते हैं. उन्हें कुछ नहीं होता. गंगा यमुना और लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के संगम में नहा कर लोग अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं. उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके पापों का नाश हो चुका है. हालांकि मेरी अपनी निजी मान्यता यह है कि अगर कोई पापी है, तो वह यह सोचे कि संगम में डुबकी लगाने मात्रसे उसके पाप खत्म हो गए, तो यह भरम है. हाँ,इतना जरूर है कि पापी व्यक्ति संगम में डुबकी लगाने के साथ यह संकल्प करें अब से वह कोई पाप नहीं करेगा,तो उसके पुराने पाप खत्म हो सकते हैं. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संगम में डुबकी लगाने के बाद वह फिर से पाप कर्म शुरू कर दे. ऐसे व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर वह कर क्या रहा है. कुंभ आत्म परिष्कार का एक अवसर है. कुंभ हमारी सांस्कृतिक यात्रा का एक पड़ाव है. कुंभ हमारी सनातन परंपरा का अद्भुत प्रकल्प है. जिसे देखने, महसूस करनेऔर उस पल को जीने के लिए दुनिया भर से भारतीय और विदेशी प्रयागराज पहुंचते हैं. लोग अपने-अपने हिसाब से वहां तरह-तरह के अनुष्ठान करते हैं. मुंडन करवाना, जनेऊ संस्कार तथा यज्ञ आदि करवाते हैं. कुल मिलाकर एक प्राचीन परंपरा का नाम है कुंभ, जहां पहुंचने वाले व्यक्ति को अपने धर्म प्राण होने का बोध होता है. इसमें दो राय नहीं की आत्मा भी निर्मल होती है. जब हम धर्म कर्म करते हैं तो हृदय को निर्मल करके जीने का भी यत्न करते हैं. का संदेश भी है. हमारा जीवन सत्कर्मों के कुंभ से भरा रहे. पाप का कुंभ वहां फूट जाए और सत्कर्मों का कुंभ लबालब भर जाए. प्रयागराज पर्यटन की जगह नहीं है. वह हृदय को पवित्र करने की जगह है. इस बार महाकुंभ है तो उम्मीद की जाती है कि यह कुंभ पूरे देश के लिए शुभ साबित होगा. पूरी दुनिया का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना भी महाकुंभ कर रहा है. बस अनुरोध यही किया जा सकता है कि हृदय रोगी वहां न जाएँ. जाएँ तो बिल्कुल सुबह डुबकी न लगाएं. इसी कारण कुछ बुजुर्गों की वहां मृत्यु हो चुकी. श्रद्धा अपनी जगह है और स्वास्थ्य अपनी जगह. प्रयागराज का यह सांस्कृतिक महाकुंभ विश्व में भारत की एक बेहतर छवि निकलने का एक सुंदर उपक्रम भी है।

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में जनता-जनार्दन का वही अटूट विश्वास हम फिर अर्जित करेंगे: देव

रायपुर। एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में भारी संख्या में उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक लोकप्रियता अर्जित मासिक प्रसारण मन की बात की 118वीं कड़ी सुनने के बाद श्री देव ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक चर्चा की। इस दौरान इन्होंने मीडिया के साथियों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

देव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है और यहाँ 1 जनवरी से लेकर 31 दिसम्बर तक सतत संगठनात्मक कार्यक्रम चलते रहते हैं। वर्तमान में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संविधान गौरव अभियान और आगामी दिनों में शुरू होने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न श्रद्धेय अटलबिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आगामी निकट भविष्य में होने जा रहे नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में भी पार्टी पंचायत से पार्लियामेंट तक का लक्ष्य लेकर जनता के बीच जाएगी और प्रधानमंत्री श्री मोदी की केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री साय की प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों, योजनाओं व उपलब्धियों से जन-जन को अवगत कराएगी। देव ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश की जनता-जनार्दन का वही अटूट विश्वास हम फिर अर्जित करेंगे, जो पिछले विधानसभा, लोकसभा और रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भाजपा के प्रति व्यक्त हुआ है। देव ने मीडिया जगत से अनौपचारिक चर्चा के इस क्रम को नियमित करने का भरोसा भी दिया।

इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश के जबलुपर से भाजपा विधायक अभिलाष पांडेय,भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा , केदारनाथ गुप्ता, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी व सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल,भाजपा रायपुर (शहर) जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर,रायपुर जिला (शहर) महामंत्री सत्यम दुवा, मुकेश शर्मा, अमरजीत छाबड़ा, पैनलिस्ट सुनील चौधरी, तौकीर रजा, डॉ. किरण बघेल, कृतिका जैन आदि उपस्थित रहे।

'भाजपा राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाली पार्टी है : नितिन नबीन

रायपुर। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने छत्तीसगढ़ प्रांत के सबसे पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष घोषित करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व व सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि आपने विधानसभा और लोकसभा का चुनाव पूरे संघर्ष के साथ जीता। आपने उन विषम परिस्थितियों में संघर्ष कर कर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है। अब नई भूमिका में आप आने वाले हैं लेकिन पुरानी भूमिका में आपने जो संघर्ष किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव आपकी ऋणी रहेगी। श्री नबीन ने कहा कि जो आने वाला चुनाव है, पंचायत से पार्लियामेंट का जो सपना हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देखा है, उस सपने को साकार करना है। इसके लिए हम सबको इस प्रकार से मिलकर चुनाव लड़ना है जिस प्रकार से हमने विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा है। एक-दूसरे का हाथ पकड़कर अपने कार्यकर्ताओं को मुखिया से लेकर मेयर तक बनाने का सपना हम सबको पूरा करना है।

श्री नितिन नवीन ने प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर किरण सिंह देव को बधाई देते हुए आगामी सफलतम कार्यकाल की शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा कि हम सभी को विश्वास है कि किरण जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमेशा की तरह परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे एवं भाजपा संगठन को नई ऊंचाइयां देंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाली पार्टी है एवं इसका एक-एक कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए समर्पित होकर कार्य करता है छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छुए सभी का यही संकल्प है। 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने के सपने को हमें छत्तीसगढ़ को विकसित बनाकर सरकार करना है।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

कांग्रेस की बैठक में 35 विधायकों में 12 विधायक रहे गायब

रायपुर। नगरीय निकाय और पंचायत की तारीखों की घोषणा से पहले सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में राजीव भवन में विधायकों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एआईसीसी सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी जरिता लैतफलांग, एआईसीसी सह-सचिव एवं सह प्रभारी विजय जांगिड़, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर, अमितेश शुक्ल, गुरू रूद्र कुमार, अमरजीत भगत और अनिला भेड़िया के साथ 23 विधायक शामिल है। कांग्रेस विधायकों की संख्या 35 है लेकिन 12 विधायक इस महत्वपूर्ण बैठक से गायब रहे इस बात की चर्चा बैठक में होते रही। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी तो वह वादे कौन-कौन से होंगे और इसका कितना लाभ चुनाव में पार्टी को मिलेगा, जनता इससे कितनी संतुष्ट होगी। इसके अलावा महापौर पद के साथ ही पार्षद प्रत्याशियों और पंच से लेकर सरपंच के पद पर किसे मैदान में उतारा जाना चाहिए।

मंत्री के इशारे पर हुई शिक्षकों के साथ पुलिस की बर्बरता

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मरीन ड्राइव में धरना दे रहे बर्खास्त बीएड धारी महिला शिक्षकों के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा के इशारे पर आधी रात को पुलिस ने बर्बरता किया। ये बेहद आपत्तिजनक एवं निंदनीय है। महिलाओं का हाथ, पैर पकड़कर जोर जबरदस्ती उन्हें सड़को पर घसीट गया। इस दौरान पुलिस के कुछ जवान नशे में झूम रहे थे, ये साफ-साफ वीडियो में दिख रहा है। जहाँ पर महिला शिक्षक समूह में बैठी दिख रही है उनके ऊपर पुलिस के जवान कूद रहे है। पुलिसिया बर्बरता के चलते कई महिलाओं को चोट आयी है, उनके कपड़े फट गये, कुछ महिलाएं बेहोश हो गई। भाजपा सरकार बर्खास्त महिलाओं शिक्षकों को पुलिसिया ख़ौफ़ दिखा कर डराना चाहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटियाँ डरेगी नहीं, कांग्रेस पार्टी बर्खास्त शिक्षकों को तत्काल वापस नौकरी देने की मांग करती है। भाजपा की सरकार देश की पहली सरकार है जो नियमित रूप से नौकरी कर रहे लोगों को बर्खास्त की है। प्रदेश के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी है, 57 हजार से अधिक से अधिक पद रिक्त है सरकार चाहे तो इन बर्खास्त शिक्षकों को वहां पर नौकरी दे सकती है पर सरकार की मंशा नौकरी देने की नहीं बल्कि नौकरी छीनने की है।

शासकीय विश्रामगृहों में नहीं ठहर पायेंगे राजनैतिक दल

रायपुर । नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के लिए कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि में किसी भी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारियों आदि को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्रामगृहों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में चुनाव प्रचार-प्रसार या राजनैतिक उद्देश्य से नहीं ठहराया जायेगा। ऐसे राजनैतिक व्यक्ति इन स्थानों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए भी नहीं कर सकेंगे। इस बारे मे कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव कुमार सिंह ने जरूरी आदेश भी जारी कर दिया है। जारी किए गए आदेश के पात्रता अनुसार स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में कमरा उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पात्रतानुसार ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद भी दी जायेगी। विश्राम गृहों में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें आगंतुक का नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन, ली गई राशि आदि समस्त ब्यौरा अंकित किया जाएगा। अधिक अवधि के लिए कोई कक्ष आरक्षित नही होगा। शासकीय भवनों, विश्राम भवनों तथा गेस्ट हाउसों का आरक्षण अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और अन्य स्थानों पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

संपत्ति के विरूपण पर की जाए कार्यवाही : कलेक्टर

रायपुर । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, इस दृष्टिकोंण से यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले में किसी संपत्ति का विरूपण न हो। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों को कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अनुसार छत्तीसगढ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, झंडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। टीम गठित करने का कार्य नगर निगम क्षेत्र में संबंधित आयुक्त, श्शेष नगरीय निकायो मे संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायतों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा समन्वय के माध्यम से किया जाये।

लाइसेंस धारकों को अपने अस्त्र-शस्त्र जमा करने के निर्देश

रायपुर । जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी डॉ गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा हेतु (सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक पीस) साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा (फोर पब्लिक सेफ्टी) हेतु सीमित अवधि के लिये रायपुर जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र लायसेंसधारियों से जमा करवा लेना उचित समझता हूँ ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। अतः आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लॉज (बी) एवं धारा 21 तथा शस्त्र नियम 2016 के नियमों के तहत रायपुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त लायसेंसधारियों को निर्देशित करता हूँ कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करें। यह आदेश जिले में निवासरत तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसधारी पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंस धारी नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के परिणामों की घोषणा उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल संघ व जिला राइफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों पर सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे।

निकाय चुनाव 2025 — भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मूलमंत्र

पंच से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपामय हो: जम्वाल

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में सोमवार को नगरीय निकाय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आवश्यक बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया. क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी चयन पूरी पारदर्शिता से करती है. इसमें किसी प्रकार का कोई अपना-पराया नहीं किया जाता है. हमें चुनाव में सही प्रत्याशी को उतारना है और उसके लिए काम भी करना है. जिसको भी टिकट मिलेगी सब मिल-जुलकर उसके साथ खड़े होंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे. इस चुनाव का जो हमारा नारा रहेगा 'हम जीतेंगे' और यह संकल्प लेकर इसे पूरा करना है.

अजय जम्वाल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है. इसके जो विचार है इसके जो चलने वाले हैं उनके मन में कांसेप्ट क्लीयर रहता है. यह हमारा वैचारिक आंदोलन है और इस आंदोलन को लेते हुए हमें आगे बढ़ाना है. देश स्वावलंबी बने, आर्थिक महाशक्ति बने, विश्वगुरु बने और दुनिया की एक महाशक्ति बने, यह हर कार्यकर्ता का सपना होना चाहिए और उसे पूर्ण करने का संकल्प हमारे वैचारिक संगठनों ने लिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण दुनिया में अपने विचार को स्वीकार्यता मिल रही है. प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में है. आज 162 देशों ने योग की शक्ति को पहचाना है. प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत से 10 सालों में 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. देश में हर घर को केन्द्र सरकार की किसी न किसी 8 से 10 योजनाओं का लाभ मिला है.

क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने कहा कि हमें आगामी चुनाव में अपने लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली शक्तियों से भी सावधान रहना है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनती, परिश्रमी एवं निष्ठावान होते हैं. हमारी भाग्य रेखा में मेहनत करना लिखा हुआ है. हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटे 24 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं. यह चुनाव जीतने का मतलब यह है कि अगर हम पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक जीतते हैं तो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, इसका लाभ सभी को मिलेगा और जो हम विकास की, विचार की, स्वावलंबन की बात करते हैं, यह सब बातें जमीनी स्तर तक हर घर तक पहुंचेगी. प्रधानमंत्री कहते हैं, 2047 तक विकसित भारत बनाना हमारा लक्ष्य है। 100 वर्ष आजादी के हम पूर्ण करेंगे और यह देश स्वावलंबी भारत होगा, यह देश विश्व गुरु भारत होगा.

प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने कहा कि चुनाव की तैयारी को लेकर यह बैठक आहूत की गई. मंडल स्तर एवं जिला स्तर पर कमेटी बनी है. त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की दृष्टि से हमारी कमेटियां बनी है. चुनाव के समय में प्रत्याशी का चयन महत्वपूर्ण विषय रहता है और जैसे चयन करेंगे, वैसा इसका परिणाम भी मिलता है. हमें सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत के लिए भाजपा का जो कार्यकर्ता लगातार कार्य कर रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश एक राज्य एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है.: शर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. इस ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ देश में वन स्टेट-वन इलेक्शन लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है. इसे लेकर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जिस तरह से हमारा देश एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी वन स्टेट-वन इलेक्शन का निर्णय लिया है. छत्तीसगढ़ प्रदेश एक राज्य एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

कांग्रेस ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम तिथि को लेकर सवाल उठाया है. कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि तीन अलग-अलग चरण में पंचायत चुनाव का परिमाण क्यों जारी किया जा रहा है, इससे परिणाम प्रभावित हो सकता है.

एक साथ 24 फरवरी को परिणाम जारी किया जाए. इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि हर बार इसी तरह होता है. पिछली बार उनकी सरकार थी तब भी हुआ था. अमला एक भाग में चुनाव कराकर दूसरे भाग में जाता है, क्योंकि पंचायती राज में वहीं पर वोटिंग और वहीं पर शाम तक मतगणना होती है. यही प्रक्रिया चल रही है. इस कारण से अधिक बल की जरूरत पड़ती है.इस चुनाव में बहुत कम समय है, इसे कितना चुनौती मानते हैं. इस सवाल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, राजनीतिक कार्यकर्ता मैं भी हूं. इस बात को बखूबी समझता हूं. निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीख बता दी है. इस पर हमको काम करना है. चुनाव के दिन कोई काम नहीं कर करता. सालों साल की मेहनत होती है तब जाकर कोई निर्णय जनता देती है.आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं, यह चुनाव कितना कठिन होता है. इस पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, पंचायती राज का चुनाव बहुत मजेदार होता है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.